

: ब्रीफ बॉक्स :

केरल हाईकोर्ट का पूर्व सीएम के खिलाफ एफआईआर का आदेश



तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार केस में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ F.I.R दर्ज करने का आदेश दिया। इस केस में पिनराई विजयन और उनकी बेटी टी वीणा पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मामला कोचीन मिनरल्स एंड स्टाइल लिमिटेड (CMRL) और वीणा की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच वित्तीय लेन-देन से जुड़ा है। कोर्ट में याचिका देकर इस मामले में F.I.R की मांग की गई थी, जिसके बाद जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने यह फैसला लिया। दरअसल, इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रही थी और उसने केरल पुलिस के साथ भी इसकी जानकारी साझा की थी। इसके बाद भी राज्य पुलिस ने F.I.R दर्ज करने के बजाय विशेष जांच टीम (SIT) बनाई थी।

नकली दवाओं का सिंडिकेट तुर्किये से अजरबैजान तक



बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक में नकली दवा बनाने वाले गिरोह की जांच में विदेश तक फैले नेटवर्क का पता चला है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के मुताबिक, गिरोह का सरगना आर. प्रशांत रंजन बाबू तुर्किये से फाइजर की दवाओं के लेबल मंगवाता था। प्रशांत अजरबैजान में रह रहा था। गिरोह इन लेबल और क्यूआर कोड की नकल कर नकली लेबल तैयार करता था। इन्हें स्कैन करने पर भी नकली होने का आसानी से पता नहीं चलता था। जांच में फाइजर के लेबल वाली करीब 10 हजार शीशियां मिली हैं। वहीं, बेंगलुरु में 18 अगस्त को बिदादी और दोड़ुरी में छापेमारी के दौरान करीब 5 करोड़ रुपए की नकली दवाएं, बिल, इंजेक्शन भरने के उपकरण और नकली लेबल मिले थे। मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नकली कैसर दवा गिरोह के तात्तुकिये और चीन से जुड़े मिले थे नकली दवाओं के खिलाफ इंटरपोल के ऑपरेशन पांजिया में भी सामने आया है कि दवा कंपनियों के नाम और पैकेजिंग की नकल कर नकली दवाओं की अंतरराष्ट्रीय सप्लाई हो रही है।

मस्क ने पूछा- स्टारलिंग को भारत में लाइसेंस क्यों नहीं, वया अंबानी असली बॉस हैं

राहुल बोले- वेलकम इलॉन, दूसरे शब्दों के मिलने तक इंतजार कीजिए



नई दिल्ली, एजेंसी। इलॉन मस्क ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंग को लाइसेंस नहीं मिलने पर सवाल उठाए हैं। मस्क ने गुरुवार को एक्स पर लिखा कि स्टारलिंग को दुनिया के 165 से ज्यादा देशों में सेवा देने की मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी पिछले पांच साल से भारत सरकार के हर कानून और जरूरी शर्त का पालन कर रही है। इसके बावजूद उसे भारत में लाइसेंस क्यों नहीं मिला है क्या अंबानी देश के रियल बॉस हैं मस्क के सवाल पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए एक्स पर लिखा- भारत में आपका स्वागत है, इलॉन। दूसरे शब्दों के मिलने तक इंतजार कीजिए। राहुल गांधी के जवाब पर इलॉन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा- धन्यवाद, राहुल। यह वाकई परेशान करने वाला है। राहुल के जवाब के मायने- जब इलॉन मस्क ने मुकेश अंबानी का नाम लेकर सवाल उठाया था, तो राहुल गांधी ने मस्क को जवाब देते हुए कहा कि अभी तो आपने सिर्फ एक (अंबानी) का नाम लिया है।

सीएपीएफ अफसरों की भर्ती-सेवा का नया कानून लागू

5 सुरक्षा बलों में आईपीएस का डेपुटेशन-प्रमोशन हो सकेगा; कैडर अफसर बोले- आगे बढ़ने के मौके खत्म होंगे



नई दिल्ली, एजेंसी। देश में सीएपीएफ (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) एक्ट 2026 लागू हो गया। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, यह कानून 8 अक्टूबर से प्रभावी है। नया कानून, सीएपीएफ में ग्रुप-ए जनरल इयूटी और दूसरे अधिकारियों की भर्ती, प्रमोशन, डेपुटेशन और सेवा शर्तों का एक जैसा ढांचा तय करता है। कानून ऐसे समय लागू हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट में हजारों सीएपीएफ अफसर इसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। यह कानून संसद ने अप्रैल में पास किया था।

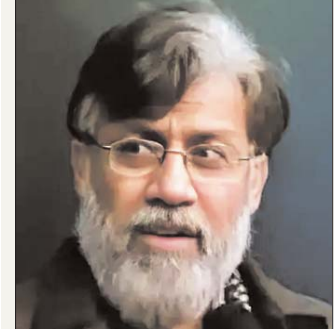
यह कानून केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीएपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) में अफसरों की भर्ती और सेवा नियमों को नियंत्रित करेगा। इसके तहत IPS से डेपुटेशन यानी प्रतिनियुक्ति के जरिए अफसरों की नियुक्ति भी की जाएगी।

कैडर अफसरों ने जताई आपत्ति-इन बलों के कैडर अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने एक अवमानना याचिका भी दाखिल की है।

सुपर-डुपर अल नीनो से पूरी धरती लाल: 76 साल में सबसे ज्यादा गर्म समुद्र

एनआईए कोर्ट में 16 नवंबर से तहखुर राणा की सुनवाई

अभी तिहाड़ जेल में बंद; मुंबई हमले का मास्टरमाइंड



नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की विशेष NIA कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहखुर राणा के मामले में आरोपों पर दलीलों के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की है। विशेष NIA जज प्रशांत शर्मा ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की।

कोर्ट ने राणा की गिरफ्तारी के बाद दाखिल सल्लोमेट्री चार्जशीट और NIA की पहले की चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद यह फैसला लिया। अभी राणा तिहाड़ जेल में बंद है। राणा को 10 अप्रैल 2025 को अमेरिका से भारत लाया गया था। तहखुर राणा को अमेरिका के शिकागो में अक्टूबर 2009 में FBI ने

कोर्ट ने बेटी से फोन पर बात करने की अनुमति दी थी- पहले राणा को कानूनी सहायता के लिए वकील पीयूष सचदेवा दिए गए थे। हालांकि, राणा ने अपनी पसंद के वकील से पैरवी कराने की इच्छा जताई, जिसके बाद सचदेवा को मामले से हटा दिया गया। इससे पहले 30 जुलाई को पटियाला हाउस परिसर स्थित विशेष हद्द कोर्ट ने राणा को बेटी से फोन पर बात करने की अनुमति दी थी। राणा ने बेटी और पत्नी से फोन पर बात करने की अनुमति मांगी थी। पाकिस्तानी मूल का बिजनेसमैन है तहखुर राणा 64 साल के तहखुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उस पर पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली की मदद करने का आरोप है।

गिरफ्तार किया था। उस पर मुंबई के 26/11 और कोपेनहेगन में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान मुहैया कराने का आरोप था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली की गवाही के आधार पर तहखुर राणा को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

बाढ़-सूखा और बीमारियों का खतरा, 4.5 लाख मौतों की आशंका

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया इस समय बेहद ताकतवर अल नीनो का सामना कर रही है। प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र का तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री ज्यादा हो गया है। यह 1950 के बाद का सबसे खतरनाक अल नीनो बताया जा रहा है। मौसम विशेषज्ञ इसे 'सुपर-डुपर अल नीनो' कह रहे हैं। इससे दुनिया के कई हिस्सों में ज्यादा गर्मी, सूखा या भारी बारिश हो सकती है। शिकागो यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब के शोधकर्ताओं के मुताबिक, इस अल नीनो से जून 2026 से फरवरी 2027 के बीच लाख अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं।

● दिसंबर में पीक पर रहेगा अल नीनो- इस साल अल नीनो दिसंबर में अपने चरम पर पहुंच सकता है। इसके असर से आने वाले महीनों में दुनिया के बड़े हिस्से में सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की आशंका है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने बारिश का पैटर्न बदलने से कई इलाकों में सूखा और बाढ़ का खतरा बढ़ने की चेतावनी दी है। डब्ल्यूएमओ के मुताबिक, अक्टूबर से दिसंबर के बीच इसका असर उत्तरी गोलार्ध में 2027 के वसंत तक बना रह सकता है। संगठन ने फरवरी 2027 तक इसके जारी रहने की करीब 100% संभावना जताई है।

हरिद्वार, मेरठ में ओले गिरे, गाड़ियों के शीशे टूटे

लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ-आदि कैलाश मार्ग बंद; बिहार के 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट



कोई हिस्सों में ज्यादा गर्मी, सूखा या भारी बारिश हो सकती है। शिकागो यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब के शोधकर्ताओं के मुताबिक, इस अल नीनो से जून 2026 से

मुजफ्फरनगर में भी ओले गिरे। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।

लखनऊ में गोमती नदी उफान पर है। इससे करीब 10 गांव बाढ़ में घिर गए हैं। 40 हजार से ज्यादा घर आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं। 3 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है।

बिहार के 18 जिलों में बारिश और आंधी को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, पटना, नालंदा, गया, नवादा, शेखपुरा समेत अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है।

भोपाल/पटना/लखनऊ/देहरादून, एजेंसी। उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, हल्द्वानी और रामनगर में शुक्रवार को बारिश हुई है। हरिद्वार में ओले गिरे, जिससे गाड़ियों के शीशे टूट गए। आज सुबह हेमकुंड साहिब और पिथौरागढ़ के धारचूला की व्यास घाटी के कुटी गांव में बर्फबारी हुई है। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग टंगड़ी-पागल नाले के पास लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया है। पिथौरागढ़ में

योगी कैबिनेट का फैसला: पीएम मोदी के नाम से जाना जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, बिना परीक्षा जॉइनिंग मिलेगी



लखनऊ, एजेंसी। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। सीएम योगी ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा- यूपी कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास कर दिया गया है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया- अब नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी के बाद नाम बदल जाएगा। यह दूसरा

मामला होगा, जब किसी सार्वजनिक प्रतिष्ठान का नाम मोदी के नाम पर रखा जाएगा। इससे पहले 24 फरवरी, 2021 को गुजरात के अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया था।

पीएम मोदी ने 28 मार्च 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज-1 का उद्घाटन किया था। एयरपोर्ट के पहले फेज में 3300 एकड़ जमीन पर टर्मिनल और रनवे बनाए गए हैं। यहां से

● योगी बोले- पीएम मोदी और यूपी का रिश्ता बहुत गहरा- कैबिनेट की बैठक के बाद योगी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 13 साल में पहला मौका था, जब मंत्रिपरिषद की बैठक के सीएम मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा- पीएम मोदी के जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने बताया- पीएम मोदी और यूपी का रिश्ता आत्मीय है, जो लगातार गहरा हुआ। उन्होंने यूपी के विकास को प्राथमिकता दी। इसके चलते प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। पीएम ने राष्ट्र निर्माण को अपना ध्येय बनाया और भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई।

हर साल लगभग 1.2 करोड़ यात्री सफर करेंगे। इस पर 11 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

शुक्रवार सुबह 11 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सीजेपी का प्रदर्शन आज

पुलिस ने कहा- परमिशन नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। कॉंकरोच जनता पार्टी के कल दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन को पुलिस की मंजूरी नहीं है। यह जानकारी शुक्रवार को जॉइंट सीपी नूपुर प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि CJP ने 7 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन करने की सूचना दी थी। तय गाइडलाइन के अनुसार 10 दिन पहले आवेदन देना जरूरी है। उन्होंने बताया, 'एहतियात के तौर पर 10 अक्टूबर को राजधानी के 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का फैसला लिया गया है।' यह भी जानकारी है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में रखने के लिए 10 डिस्टेंशन सेंटर बनाए हैं। उधर, न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें कल कैप्सिल रहेंगी। रेलवे ने इन ट्रेनों को उनके शुरुआती स्टेशनों से ही रद्द कर दिया है।

दिल्ली में 2020 दंगों के बाद सबसे बड़ी सुरक्षा तैयारी

10 अक्टूबर को प्रस्तावित सीजेपी के प्रदर्शन के पहले दिल्ली में 26 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। यह 2020 के दिल्ली दंगों के बाद सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी तैनाती बताई जा रही है। इनमें पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 15 हजार जवान भी शामिल होंगे। मेट्रो ट्रेन-इंटरनेट बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल दिल्ली में कल मेट्रो और पैसंजर ट्रेनें और इंटरनेट बंद करने के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की गई। इनका आरोप है कि इससे लोगों को परेशानी होगी।

सीजेपी के जंतर-मंतर प्रदर्शन में हिंसा की जांच दोबारा होगी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 20 जुलाई को राजधानी में कॉंकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की हालात की जांच के लिए एक नई एफआईआर दर्ज की है।

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सूत्रों का दावा है कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी। उक्ताने वालों की पहचान की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि क्या यह पहले से रची गई सोची-समझी साजिश थी।

दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर 'फ्री हैंड' देने की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- छात्रों के भविष्य का भी रखें खयाल

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पूरी छूट देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में युवाओं और छात्रों के भविष्य को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने बड़ी टिप्पणी करते हुए युवाओं के भविष्य पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने ये युवा छात्र और

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे टिप्पणी की कि हमें उनके माता-पिता के बारे में सोचना होगा, यह भी देखना होगा कि उनका लंबा जीवन बाकी है। वे अनावश्यक रूप से अदालती चक्करों और मुकदमों में नहीं फंसेना चाहिए। 'गंभीर अपराधों पर नरमी नहीं' हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग कथित तौर पर कुख्यात अपराधी हैं या जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं।

प्रदर्शनकारी हैं।

संक्षिप्त समाचार

मुंबई में 18 दिसंबर से होगी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, उद्घाटन सत्र को मोहन भागवत करेंगे संबोधित



मुंबई, एजेंसी। दुनियाभर के हिंदू नेतृत्व, विचारकों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का वैश्विक समागम वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस (डब्ल्यूएचसी) 2026 इस बार मुंबई में होगा। तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 18 से 20 दिसंबर तक बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा।सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ससंघचालक डॉ. मोहन भागवत संबोधित करेंगे। आयोजकों के अनुसार, सम्मेलन में 60 से अधिक देशों के चार हजार से ज्यादा प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें हिंदू नेता, विचारक, उद्यमी, शिक्षाविद, मीडिया प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर एक मंच पर जुटेंगे। तीन दिनों में 45 से अधिक सत्र होंगे और 150 से अधिक वक्ता अपने विचार रखेंगे। सम्मेलन अर्थव्यवस्था, शिक्षा, अकादमिक जगत, मीडिया और राजनीति जैसे क्षेत्रों में हिंदू समाज की भूमिका को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सम्मेलन में भाषा, समाज और धर्म विषयों पर विशेष सत्र होंगे। सम्मेलन के साथ पहली बार वर्ल्ड हिंदू एक्सपो भी आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य व्यापार-वाणिज्य और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस इससे पहले 2014 में नई दिल्ली, 2018 में शिकागो और 2023 में बैंकाक में आयोजित हो चुका है।

बंगाल में मुर्शिदाबाद के मदरसे में दो छात्रों का यौन उत्पीड़न, संचालक दंपती गिरफ्तार; इमारत बंद की मांग उठी



कोलकाता, एजेंसी। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित एक अवैध मदरसे में दो नाबालिग छात्रों के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप मदरसे में पढ़ने वाले पांच नाबालिग छात्रों पर लगा है। पुलिस ने आरोपित छात्रों को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है, जिसमें उक्त मदरसे के संचालक के दो बेटे भी शामिल हैं। घटना की जानकारी होने पर भी कोई कदम नहीं उठाने के आरोप में संचालक और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सागरपाड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाले 10 वर्षीय छात्र ने लगभग एक महीने पहले मदरसे में दाखिला लिया था। आरोप है कि वहां संचालक दंपती के दो बेटों समेत पांच छात्रों ने उसके साथ कई दिनों तक यौन उत्पीड़न किया। पीड़ित छात्र को घटना के बारे में किसी को बताने पर डराने-धमकाने और पीटने का आरोप है। हाल में छात्र ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। इसके बाद छात्र की मां एक स्वयंसेवी संस्था की कार्यकर्ता को लेकर मंगलवार को मदरसा पहुंचीं और संचालक को घटना की जानकारी दी। वहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो एक अन्य नाबालिग छात्र के साथ भी लंबे समय से इसी तरह के यौन उत्पीड़न का आरोप सामने आया। मामला सामने आने के बाद उक्त मदरसे को बंद करने की मांग उठी है।

पाल-देवल में मतदाता पंजीयन अभियान: 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं के पंजीकरण का लक्ष्य शत-प्रतिशत हासिल

डुंगरपुर, एजेंसी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर देशलदास के निर्देशन में पात्र युवाओं को मतदाता सूची में पंजीकृत करने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं जिला स्वीप टीम के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को पंचायत समिति पाल-देवल में मतदाता पंजीयन अभियान चलाया गया। अभियान के तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पात्र युवाओं के मतदाता पंजीयन का निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत हासिल किया गया। अभियान के दौरान जिला स्वीप टीम के सदस्यों, संबंधित पीईईओ एवं बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलए) ने पात्र युवाओं के पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई। युवाओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवश्यक कार्यवाही की गई, ताकि कोई भी पात्र युवा मतदाता सूची में पंजीकरण से वंचित न रहे। अभियान का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी पात्र युवाओं को मतदाता सूची में पंजीकृत कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लाना तथा मतदाता सूची में पात्र नागरिकों की शत-प्रतिशत भागीदारी रही। अभियान के माध्यम से युवाओं को उनके मतधिकार के महत्व के प्रति जागरूक करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने की अपील की गई।

मेरे आस-पास शराबी लोग हैं..., असम की छात्रा का परिवार को आखिरी मैसेज, रेलवे ट्रैक पर मिली लाश

गुवाहाटी, एजेंसी। असम की 20 साल की छात्रा डॉस कॉम्पिटिशन के बाद ट्रेन से अकेले यात्रा कर रही थी। परिवार का 6 अक्टूबर की सुबह से उससे संपर्क टूट गया था। बुधवार, 7 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में रेलवे ट्रैक के पास उसका शव मिला। अब इस 20 साल की छात्रा का गायब होने से पहले का आखिरी वीडियो सामने आया है। छात्रा ने अपने परिवार को बताया था कि उसके कोच में नशे में धुत लोग हैं, जिसकी वजह से उसे डर लग रहा है।

छात्रा का गायब होने से पहले का आखिरी वीडियो: छात्रा के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है और रेलवे सुरक्षा बल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसकी मौत की परिस्थितियों की गहन जांच की मांग की है। परिवार ने आखिरी कॉल और वीडियो के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी बेटी ने कहा था कि



असम 'मेरे आस-पास शराबी लोग हैं...' असम की छात्रा की संदिग्ध मौत

ट्रेन के डिब्बे में नशे में धुत लोगों की वजह से उसे अमरुक्षित महसूस हो रहा है। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक, उनकी बेटी 6 अक्टूबर को रात करीब 12:15 बजे

भाभी को मिलाया आखिरी कॉल: रेलवे ने बताया कि फुटेज में बोरो जनरल टिकट के साथ ट्रेन के २-2 कोच में चढ़ती हुई दिखाई दी। इसके बाद छात्रा ने अपनी भाभी को कॉल किया। छात्रा की भाभी ने कहा, 'ट्रेन में चढ़ने के बाद, उसने मुझे और अपनी एक अन्य दोस्त को फोन किया और बताया कि उसे कोच में असहज महसूस हो रहा है। उसके आस-पास नशे में धुत आदमी थे, जिससे उसे अमरुक्षित महसूस हो रहा था। छात्रा ने अपनी एक दोस्त के साथ कोच का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें कोच के अंदर के हालात नजर आए, जिनका जिक्र उन्होंने कॉल के दौरान किया था। परिवार ने बताया कि रात 2.30 बजे से 3 बजे के बीच उनका अपनी बेटी से संपर्क टूट गया और इसके बाद उन्होंने रेलवे हेलपलाइन को सूचना दी। उन्हें बताया गया कि आरपीएफ के कर्मचारी उसकी जांच करेंगे।घटना के बाद

भाभी ने बताया, 'हमें उसके सुरक्षित होने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब उसका शव आंध्र प्रदेश में रेलवे ट्रैक के पास मिला है। कोच के अंदर उसके दो बैग सही-सलामत मिले हैं।'

मामले की जांच जारी: नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने कहा कि परिस्थितियों की जांच चल रही है और पलासा में सरकारी रेलवे पुलिस की शुरुआती जांच से पहली नजर में पता चलता है कि बोरो चलती ट्रेन से गिर गई होगी। उसे 6 अक्टूबर को 'रेल मदद' पोर्टल के जरिए ट्रेन में एक महिला यात्री के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिली थी। एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर और अन्य कर्मचारियों ने श्रीकाकुलम रोड स्टेशन पर शिकायत पर कार्रवाई की। रेलवे ने बताया कि उन्होंने जनरल और स्लीपर कोच की तलाशी ली, लेकिन छात्रा का पता नहीं चल सका।

दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिए गए 10 हजार से ज्यादा लोग, अभिजीत दीपके का दावा

नई दिल्ली, एजेंसी। काँकरोच जनता पार्टी ये एलान कर चुकी है कि 10 अक्टूबर को वे दिल्ली के जंतर-मंतर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। प्रवक्ता आशुतोष रंका ने इस प्रदर्शन से पहले आज शुक्रवार को दावा किया है कि प्रोटेस्ट से पहले देशभर में कम से कम 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया है। काँकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रस्तावित प्रदर्शन पर लगाई गई पाबंदियों पर सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के एक वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिजीत दीपके ने कहा, 'क्यों न सीधे इमरजेंसी ही घोषित कर दी जाए' गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दीपके ने राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक सभाओं पर लगाई गई पाबंदियों की आलोचना की।



दीपके ने कहा, 'जंतर-मंतर भारत के लोगों का है, यह केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नहीं है। अगर मुंबई और बंगलुरु में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो जा विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आ रहे थे। पार्टी के अनुसार, छात्रों को बस में बिठाकर किसी अज्ञात जगह ले जाया जा रहा था। पार्टी ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों में राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक बालियान भी शामिल थे, जिन्हें गुरुवार को पुलिस हिरासत में लिया गया और उसी रात बाद में

रिहा कर दिया गया। दिल्ली पुलिस या किसी और सोर्स ने हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या की कोई पुष्टि नहीं हुई है। **एसआईआर को लेकर बवाल:** दीपके ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। वहीं उन्होंने राजनीतिक दलों, नागरिक समाज समूहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से वोटिंग के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की। दीपके ने कहा, (सिस्टमैटिक इलेक्टोरल रोल अपडेशन) सबसे बड़ा घोटाला है जिसे केंद्र सरकार यानी सरकार भारत में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए अंजाम दे रही है।' संस्थापक ने कहा, '10 अक्टूबर को होने वाले मार्च का मकसद वोट हटाने के मामले के लिए मुख्य चुनाव अधिकृत ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराना होगा।'

आइवरी कोस्ट में जयशंकर: रक्षा और कृषि में सहयोग बढ़ाने पर जोर; किन नेताओं से हुई मुलाकात, क्या है मकसद



यामोसोऊको, एजेंसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और आइवरी कोस्ट की साझेदारी आपसी सम्मान पर आधारित है। दोनों देशों की विकास और समृद्धि के लिए साझा प्रतिबद्धता है। जयशंकर ने पश्चिम अफ्रीकी देश की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अलासाने औटारा से मुलाकात की। वह तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं। इसमें घाना, आइवरी कोस्ट और इथियोपिया शामिल हैं। जयशंकर बुधवार को घाना से आइवरी कोस्ट पहुंचे थे। यह उनकी तीन देशों की यात्रा का दूसरा पड़ाव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलासाने औटारा से मुलाकात कर सम्मानित महसूस किया। राष्ट्रपति द्रौपीदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत शुभकामनाएं उन्हें दी। विदेश मंत्री ने कहा, भारत-आइवरी कोस्ट साझेदारी आपसी सम्मान और विकास तथा समृद्धि के लिए साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। उन्होंने राष्ट्रपति औटारा को 'मजबूत, लंबे समय तक चलने वाली और दोनों के लिए फायदेमंद साझेदारी के अपने दृष्टिकोण को साझा करने' के लिए धन्यवाद दिया।

रक्षासहयोग पर क्या हुई बात: बुधवार को जयशंकर ने अविदजान में आइवरी कोस्ट के उप प्रधानमंत्री तेने बिराहिमा औटारा से भी मुलाकात की। दोनों ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग पर चर्चा की। बैठक के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने आपसी भरोसे, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित अपने बढ़ते रक्षा सहयोग पर बात की।

जंग में करोड़ों के उपकरण स्वाहा: ईरान से युद्ध में 81 अमेरिकी सैन्य विमान, ड्रोन नष्ट

वाशिंगटन, एजेंसी। ईरान के साथ सात महीने से अधिक समय से जारी युद्ध में अमेरिकी सेना को भारी क्षति पहुंच है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, इस युद्ध में अमेरिका के कम से कम 81 सैन्य विमान और ड्रोन क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं। यह जानकारी इस सप्ताह अपडेट की गई अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने भी नुकसानों को स्वीकार किया है। नष्ट हुए विमानों में वे भी शामिल हैं जिन्हें सेना ने सार्वजनिक रूप से खोया हुआ स्वीकार किया है। इनमें ईरान में दो गिरे हुए विमान चालकों को बचाने के अभियान के दौरान नष्ट हुए विमान भी थे। इसके अलावा, दर्जनों ड्रोन ऐसे भी हैं जिन पर सेना ने चर्चा करने से इनकार किया है। रिपोर्ट बताती है कि क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए 81 विमानों में 45 एमक्यू-9 रीपर ड्रोन शामिल थे। इसमें 12 एफ-15ई स्ट्राइक ईंगल जेट भी थे। साथ



ही, सात केसी-135 स्ट्रैटोटेकर हवाई ईंधन भरने वाले विमान भी नष्ट हुए। एक एफ-35ए लाइटनिंग II लड़ाकू जेट भी इस सूची में है। यह रिपोर्ट युद्ध के नुकसान की जानकारी देती है। सेना ने उपकरणों और ठिकानों को हुए नुकसान की कोई

ट्रंप ने सत्य नडेला को दिया सम्मान: कुछ घंटे पहले माइक्रोसॉफ्ट पर हुई थी कार्रवाई

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सत्य नडेला जैसे टेक अरबपतियों की तारीफ की। लेकिन इससे कुछ घंटे पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कार्रवाई का एलान किया था। कंपनी को एक ऐसे कार्यक्रम से निलंबित किया गया है, जिसके तहत कंपनियां एच-1बी वीजा वाले कुशल विदेशी कर्मचारियों के लिए ग्रीन कार्ड के आवेदन कर सकती हैं। वेंस एक धोखाधड़ी रोकेन वाली टास्क फोर्स के प्रमुख हैं। इसी के तहत माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ यह कार्रवाई हुई। इस

कार्रवाई से अमेरिका की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाली कंपनियों और प्रशासन के बीच तनाव सामने आया है। प्रशासन आव्रजन कम करना चाहता है। उसका कहना है कि इससे अमेरिकी कामगारों को नुकसान हुआ है।उपराष्ट्रपति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, माइक्रोसॉफ्ट के लिए हमारा संदेश है- आप एक महान अमेरिकी कंपनी हैं, लेकिन आपको महान अमेरिकी कामगारों को नौकरी देनी होगी। उन्होंने कहा कि कंपनी ने वीजा व्यवस्था का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने प्रश्न करने वाला रख अपनाया। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में नडेला के काम की तारीफ की। उन्होंने कंपनी में विदेशी कामगारों की नियुक्ति

को लेकर कोई बयान नहीं दिया।ट्रंप ने कहा, तीन दशक से ज्यादा समय से सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के बदलाव में एक अहम व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने कंपनी में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने दुनियाभर के कारोबारों, छात्रों और उपभोक्ताओं को अब तक बनाए गए सबसे सक्षम सॉफ्टवेयर में से कुछ उपलब्ध कराए।राष्ट्रपति से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए सम्मान पाने वाले छह टेक दिग्गजों में से पांच प्रवासी हैं। राष्ट्रपति ने स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क, गूगल के सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन, एनवीडिया के सीईओ जेंसन हुआंग और सेमीकंडक्टर कंपनी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज की

सीईओ लिसा सु को राष्ट्रीय विज्ञान पदक दिया। इन सभी का जन्म अमेरिका के बाहर हुआ है। मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ब्रिन का जन्म रूस में हुआ। हुआंग और सु का जन्म ताइवान में हुआ। नडेला के अलावा ट्रंप ने डेल टेक्नोलॉजीज के सीईओ माइकल डेल को भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक दिया। डेल ने बच्चों के लिए सरकार के खास निवेश खातों को बढ़ावा दिया है। इन खातों को ट्रंप अकाउंट्स कहा जाता है। डेल का जन्म टेक्सास में हुआ था। वहीं नडेला भारत से अमेरिका आए थे। ट्रंप ने अरबपतियों के इस समूह को 'राष्ट्रीय धरोहर' बताया।

ट्रंप लगातार कैसे बदल रहे जंग रुकवाने के आंकड़े, सच्चाई कितनी, क्या मिल सकता है शांति का नोबेल

वाशिंगटन, एजेंसी। नॉर्विजियन नोबेल समिति शांति के नोबेल पुरस्कार के विजेता का एलान करेगी। इससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की है। ट्रंप ने एक दिन पहले ही व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, 'मैंने कई ऐसी चीजों की हैं, जो किसी और ने नहीं की। मैंने आठ युद्धों का अंत करवाया है।' हालांकि, इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि नोबेल शांति पुरस्कार देने वाली समिति 2026 के पुरस्कार के लिए उनका नाम चुनेगी या नहीं। ट्रंप के इन बयानों के बाद एक बार फिर उनके दुनियाभर में 'जंग का अंत' करवाने वाले दावों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ट्रंप जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से ही लगातार एक के बाद एक युद्ध रुकवाने के दावे करते जा रहे हैं। एक समय तो उन्होंने 10 युद्ध का अंत कराने का दावा तक कर दिया था। हालांकि, अपने हालिया बयान में वे एक बार फिर दुनिया के आठ युद्ध रुकवाने के दावे पर लौट आए हैं। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कब से की जा रही है वे अब तक कब और कितनी जगों



को रुकवाने का दावा कर चुके हैं उनके दावों में कोन-कोन से युद्धों का जिक्र लगातार रहा है कैसे उनके जंग रुकवाने का आंकड़ा आठ से 10 और फिर वापस आठ पर आ गया है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनकी दावेदारी कितनी मजबूत रही है यह पुरस्कार मिलता कैसे है और ट्रंप के लिए संभावना क्या है आइये जानते हैं...पहले जानें- ट्रंप कब से कर रहे नोबेल शांति पुरस्कार की मांगडोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग पहली बार नहीं हुई है। वे अपने पहले कार्यकाल (2017-2021) से ही इस प्रतिष्ठित

सम्मान की मांग करते आ रहे हैं। **पहला कार्यकाल (2019 - 2020):** ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहना शुरू किया था कि वे इस पुरस्कार के हकदार हैं। उन्होंने दावा किया था कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ हुई शिखर वार्ता के बाद जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने नोबेल समिति को उनके नाम का पत्र भेजा था। इसी दौरान उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2009 में नोबेल पुरस्कार मिलने की आलोचना भी की थी।जब इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, तो ट्रंप ने चुनावी रैलियों में नाराजगी जताते हुए कहा था कि शांति समझौता उन्होंने करवाया था, लेकिन श्रेय किसी और को मिल गया। **दूसरा कार्यकाल (2025-2026):** व्हाइट हाउस में वापसी के बाद ट्रंप ने अलग-अलग मौकों पर दावा किया कि उनके प्रशासन ने दुनिया भर में कई युद्धों को खत्म किया है। इस्राइल, पाकिस्तान, कंबोडिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और रवांडा जैसे देशों के नेताओं ने उनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए प्रस्तावित करने का दावा किया।हालांकि, जब 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देनेजेन्युएल की विपक्षी नेता मारिया कोरीना

माचाडो को दिया गया, तो ट्रंप और व्हाइट हाउस ने नोबेल समिति के फैसले पर सवाल उठाए थे। बाद में माचाडो ने खुद यह पुरस्कार ट्रंप को समर्पित करने की बात कही थी। **नोबेल शांति पुरस्कार पर अब क्या बोले ट्रंप:** अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की है। उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, 'मैंने वो काम किए हैं जो आज तक किसी और ने नहीं किए।' मैं ईंग नहीं मार रहा हूँ, सिर्फ अपकंट डेल को बचा रहा हूँ। शायद किसी भी राष्ट्रपति ने कभी कोई युद्ध नहीं सुलझाया, लेकिन मैंने आठ युद्ध सुलझाए हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे नहीं पता कि उनका निर्णय क्या होने वाला है... उनकी ऐसी छवि रही है कि वे शायद मेरे जैसे लोगों को यह पुरस्कार नहीं देते। लेकिन मुझे यह मिले या न मिले, मैंने (पुरस्कार की तुलना में) कहीं ज्यादा काम किया है। और अगर वे इसे मुझे नहीं देते, तो यह उनके लिए एक बड़ा अनादर होगा।' ट्रंप ने नोबेल समिति से अपनी खीझ जाहिर करते हुए कहा, 'पिछली बार जिस युवा महिला (मारिया कोरीना माचाडो) को यह पुरस्कार दिया गया, वह शानदार ईसान हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि वे इसकी हकदार नहीं थीं।

सिंगरौली में 56 करोड़ से बन रहा माइनिंग कॉलेज, पहले चरण का काम अंतिम दौर में

कलेक्टर गौरव बैनल ने किया निरीक्षण, कक्षाओं में रोशनी, हवा और रैंप की व्यवस्था के निर्देश दूसरे चरण में खर्च होंगे 30 करोड़



मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले के तियरा में 56 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन माइनिंग कॉलेज के पहले चरण का काम अंतिम दौर में पहुंच गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध

करने की तैयारी की जा रही है शुक्रवार को कलेक्टर गौरव बैनल ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शेष निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और कॉलेज भवन में विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुरूप सभी

आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि भवन को केवल निर्माण की दृष्टि से पूरा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की पढ़ाई और दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं विकसित करना भी जरूरी है।

उन्होंने पेयजल, लाइब्रेरी, कक्षाओं और हॉस्टल से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। **लाइब्रेरी और कक्षाओं में होंगी जरूरी व्यवस्थाएं:** माइनिंग कॉलेज के पहले चरण में कॉलेज भवन, लाइब्रेरी और हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए व्यवस्थित स्थान तैयार करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कक्षाओं में पर्याप्त रोशनी और हवा को व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान परेशानी न हो इसके साथ ही भवन में रैंप बनाने के निर्देश दिए गए जिससे आवागमन सुविधाजनक हो सके। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि भवन को विद्यार्थियों के उपयोग के लिए तैयार करते समय इन सभी व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।

पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तलाशेंगे विकल्प: कॉलेज परिसर में पेयजल की व्यवस्था को लेकर भी कलेक्टर ने अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र में भूजल स्तर और नजदीकी तालाब में उपलब्ध पानी की स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए इसके अलावा जल निगम की नल-जल पाइपलाइन से कॉलेज तक पानी पहुंचाने की संभावनाएं तलाशने को कहा कॉलेज के नियमित संचालन के लिए पर्याप्त पेयजल व्यवस्था जरूरी है। ऐसे में अधिकारियों को उपलब्ध विकल्पों का परीक्षण कर उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। **दूसरे चरण में ऑडिटोरियम और हॉस्टल का होगा विस्तार:** माइनिंग कॉलेज के दूसरे चरण में 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस चरण में ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस,

हॉस्टल और फर्नीचर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी इससे संस्थान में विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक गतिविधियों के विस्तार में भी मदद मिलेगी। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संचप्रिय और पीआईयू की कार्यपालन यंत्री देवयानी सिंह मौजूद रहीं कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए माइनिंग कॉलेज के निर्माण से जिले में तकनीकी शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार होने उम्मीद है फिलहाल पहले चरण के शेष कार्यों को पूरा कर भवन को विद्यार्थियों के उपयोग के लिए तैयार करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

सिंगरौली में BEO फूलचंद पटेल निर्लंबित, 22 हजार साइकिलों की रसीद जारी नहीं करने पर कार्रवाई

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले के बैदुन विकासखंड शिक्षा अधिकारी फूलचंद पटेल को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में लापरवाही बरतने के आरोप में निर्लंबित कर दिया गया है विकासखंड में करीब 22 हजार साइकिलों का वितरण किए जाने के बाद भी संबंधित सप्लायर एजेंसी को रसीद जारी नहीं की गई थी इसे शासकीय कार्य में उदासीनता और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना मानते हुए लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने कार्रवाई की है निर्लंबन का आदेश 7 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया। **समीक्षा बैठक में दिए गए थे निर्देश:** जानकारी के अनुसार, जून और जुलाई 2026 के दौरान बैदुन विकासखंड में अलग-अलग तारीखों पर विद्यार्थियों को साइकिलें वितरित की गई थीं वितरण के बाद सप्लायर एजेंसी को आवश्यक रसीद जारी नहीं किए जाने का मामला सामने आया 8 जून को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान साइकिल वितरण योजना की समीक्षा की गई थी इस दौरान संबंधित कार्य में लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर विभाग ने इसे गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। **सप्लायर पर दबाव बनाने की शिकायतें:** जिला परियोजना समन्वयक आरएल शुक्ला के अनुसार, फूलचंद पटेल के खिलाफ सप्लायर पर अनुचित दबाव बनाने और साइकिलों की गुणवत्ता से समझौता करने जैसी शिकायतें भी सामने आई थीं इन शिकायतों और वितरण प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं की समीक्षा के बाद विभाग ने कार्रवाई का निर्णय लिया लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह के निर्देश पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत फूलचंद पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

सेवा संकल्प अभियान के तहत रक्तदान शिविर, SDM आकाश अग्रवाल सहित अधिकारियों-कर्मचारियों ने किया रक्तदान

आईटीआई मझौली में चलित वाहन के जरिए आयोजित हुआ शिविर, जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए लोगों ने बढ़ाए हाथ



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सेवा संकल्प अभियान एवं मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत शासकीय आईटीआई मझौली में आयोजित जिला स्तरीय शिविर के दौरान चलित वाहन रक्तदान शिविर लगाया गया शिविर में एसडीएम मझौली आकाश अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों और निजी संस्थानों से जुड़े लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस पहल के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों की सहायता

करने और समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया। शिविर में एसडीएम आकाश अग्रवाल ने स्वयं रक्तदान कर लोगों को इस सामाजिक कार्य के लिए प्रेरित किया उन्होंने अपनी सहभागिता के माध्यम से यह संदेश दिया कि रक्तदान जरूरतमंद मरीजों की मदद करने का महत्वपूर्ण माध्यम है शिविर में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की भागीदारी ने जमस्वरा और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।

अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा: रक्तदान शिविर में विकासखंड प्रबंधक ग्रामीण आजीविका मिशन चंद्रकांत सिंह, जनपद पंचायत मझौली के अरविंद तिवारी, बीसी आवास कुंवर बहादुर आजाद, मध्यांचल ग्रामीण बैंक मझौली के शाखा प्रबंधक निरंजन पासवान तथा बीमा सलाहकार काजल सिंह सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की सहभागिता से शिविर में जनसेवा की भावना देखने को मिली आयोजन के माध्यम से लोगों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि रक्तदान केवल व्यक्तिगत योगदान नहीं बल्कि जरूरत के समय किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की रक्षा में सहयोग करने का महत्वपूर्ण अवसर भी है। **जनकल्याण के साथ सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा:** सेवा

संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित इस शिविर का उद्देश्य जनकल्याणकारी गतिविधियों के साथ सामाजिक सरोकारों को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को मानव सेवा के कार्यों से जोड़ना रहा चलित वाहन के माध्यम से आयोजित रक्तदान शिविर ने लोगों को एक स्थान पर रक्तदान करने का अवसर उपलब्ध कराया मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में इस तरह की गतिविधियों को सामाजिक सहभागिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है रक्तदान करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य सहभागियों ने जरूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए योगदान दिया शिविर के माध्यम से आम नागरिकों को भी रक्तदान के प्रति जागरूक होने तथा अपनी क्षमता और चिवित्त्वकीय पात्रता के अनुसार इस जरूरतवा अभियान में भाग लेने का संदेश दिया गया।

पनवार पुलिस ने 36 घंटे में सुलझाई 13 वर्षीय रवि सेन की हत्या की गुत्थी गुमशुदगी की जांच के दौरान गजेड़ी नदी में मिला था बालक का शव, उत्तर प्रदेश के भड़िवार से बाल अपचारी गिरफ्तार



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। पनवार थाना पुलिस ने 13 वर्षीय बालक रवि सेन की हत्या के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 36 घंटे के भीतर प्रकरण का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में एक बाल अपचारी को उत्तर प्रदेश के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के भड़िवार से गिरफ्तार किया आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे

किशोर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से बाल संप्रेशन गृह भेज दिया गया पुलिस के अनुसार 5 अक्टूबर 2026 को फरियादिया रेखा सेन, निवासी चौर, थाना पनवार ने अपने 13 वर्षीय बेटे रवि सेन के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी परिजनों ने बताया कि रवि 4 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे साइकिल से गेहूं लेकर शिवपुर स्थित आटा चक्की जाने की बात

कहकर घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 222/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बालक की तलाश के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम रामबाग पियरिया के पास गजेड़ी नदी में एक शव तैर रहा है। **नदी में मिला था बालक का शव:** सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकालवाया। पहचान करने पर शव रवि सेन, पिता रजन सेन, उम्र 13 वर्ष का निकला पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवा में कराया चिकित्सक से प्राप्त शॉट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता

की धारा 103(1) और 238 भी जोड़ी गई। **सीसीटीवी और मुखबिर तंत्र से मिली मदद:** हत्या के मामले की जांच के दौरान पुलिस ने संभावित सीसीटीवी कैमरों की जांच की और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के भड़िवार से बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया उसे किशोर न्यायालय में पेश किए जाने के बाद बाल संप्रेशन गृह भेज दिया गया। **पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका:** कार्रवाई में थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल, उपनिरीक्षक शोभा सिंह, प्रधान आरक्षक रामभान पटेल, तनय तिवारी तथा आरक्षक कमल किशोर शर्मा, रमेश वर्मा, अतुल सिंह, शंभू कुमार बिंद, रिकू सिंह और सूरज पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

शहडोल में दो पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, ASI समेत दो निर्लंबित

हाईवे पर वाहन चालक से रुपए लेने का वीडियो वायरल, वारंटी की तलाश में लापरवाही का भी आरोप दोनों मामलों की जांच डीएसपी को सौंपी



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली से जुड़े अलग-अलग मामलों में पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने कार्रवाई करते हुए एक सहायक उपनिरीक्षक (ASI) समेत दो पुलिसकर्मियों को निर्लंबित कर

दिया है निर्लंबित पुलिसकर्मियों में सोहागपुर थाने के एसएसआई जवाहरलाल राय और बुढ़ार थाने के प्रधान आरक्षक चेताराम कौशिक शामिल हैं दोनों को ब्यौहारी थाने से संबद्ध किया गया है मामलों की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है।

हाईवे पर रुपए लेने का वीडियो वायरल: एसएसआई जवाहरलाल राय के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है वीडियो में वे हाईवे पर एक पिकअप वाहन को रोककर उसके चालक से कथित तौर पर रुपए लेते दिखाई दे रहे हैं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कराई है हालांकि वीडियो में दिखाई दे रही घटना और उससे जुड़े आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। **वारंटी की तलाश में लापरवाही का आरोप:** बुढ़ार

थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक चेताराम कौशिक पर एक वारंटी की तलाश के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है बताया गया है कि उन्होंने थाना प्रभारी को जानकारी दिए बिना खानगी दर्ज कराई लेकिन संबंधित वारंटी की तलाश नहीं की इसके अलावा मामले में आवश्यक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने उन्हें निर्लंबित कर दिया प्रधान आरक्षक चेताराम कौशिक से जुड़ा एक अन्य वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था इसमें वे एक महिला के साथ रेस्टोरेंट में बैठे दिखाई दे रहे हैं।

डालमिया कंपनी के जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने सौंपा ज्ञापन

प्रभावित ग्राम पंचायतों के सरपंचों और किसानों ने रीवा संभागायुक्त से की मुलाकात, जमीन और अधिकारों की रक्षा की मांग

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। डालमिया कंपनी द्वारा जमीन अधिग्रहण किए जाने के विरोध में प्रभावित किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की है। सिंहपुर पहुंचकर प्रभावित ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं किसान साथियों ने रीवा संभाग के कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से किसानों के जमीन के अधिग्रहण पर विरोध दर्ज कराते हुए प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई किसानों का कहना है कि जमीन उनके जीवनयापन और आजीविका



का प्रमुख आधार है ऐसे में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले किसानों के हितों और अधिकारों की अनदेखी

नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित किसानों

की समस्याओं पर विचार किया जाए और उनके हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए ज्ञापन

सौंपने के दौरान प्रभावित ग्राम पंचायतों के सरपंचों और किसान साथियों ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया किसानों ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के नाम पर प्रभावित होने वाले परिवारों के अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है किसी भी निर्णय में किसानों की समस्याओं, उनकी आजीविका और भविष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए किसानों ने कहा कि उनकी जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा जब तक प्रभावित किसानों

के हितों से जुड़े मुद्दों पर उचित पहल नहीं होती तब तक वे अपनी मांगों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाते रहेंगे इस दौरान किसान एकता पर जोर देते हुए सभी प्रभावित किसानों से संगठित रहने की अपील की गई ज्ञापन के जरिए प्रशासन का ध्यान जमीन अधिग्रहण से जुड़ी चिंताओं की ओर आकर्षित करते हुए किसानों को न्याय दिलाने की मांग की गई किसान एकता जिंदाबाद के नारे के साथ किसानों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प जताया।

सिंगरौली में RTE के तहत प्रवेश नहीं देने पर दो स्कूलों पर एक-एक लाख का जुर्माना

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत पात्र बच्चों को प्रवेश नहीं देने के मामले में शिक्षा विभाग ने दो निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की है। शुक्रवार को संस्कार कैली और काइस गडज हायर सेकेंड्री स्कूल पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया दोनों स्कूल प्रबंधन को जुर्माने की गति रैड्रॉस सोसाइटी के खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं विभागीय जांच में सामने आया कि दोनों स्कूलों ने प्रवेश के लिए पहुंचे पात्र बच्चों को सीटें भरी होने की बात कहकर लौटा दिया था इसके बाद खाली सीटें दिखाकर सामान्य श्रेणी के बच्चों को प्रवेश देने की अनियमितता सामने आई इसे RTE के नियमों का उल्लंघन मानते हुए विभाग ने कार्रवाई की। शिक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद संस्कार कैली स्कूल प्रबंधन ने शुक्रवार को ही एक लाख रुपये की जुर्माना गति रैड्रॉस सोसाइटी के खाते में जमा कर दी वहीं, काइस गडज हायर सेकेंड्री स्कूल ने खबर लिखे जाने तक गति जमा नहीं की थी।

नाम सुधार सूचना
मैं मनीषा साकेत आयु 42 वर्ष पत्नी श्री संतोष कुमार वर्मा निवासी ग्राम पोस्ट उमरी तहसील रायपुर कर्जुलिया जिला रीवा (MP) की मूल निवासी हूँ यह कि मेरे पुत्र स्वतंत्र गय ज्योति सौनियर सेकण्ड्री स्कूल रीवा में कक्षा 10 वीं में अध्ययनरत है जिसके विद्यालयीन दस्तावेजों में माता के नाम की स्पेलिंग गुडिश MAN-ISH SAKET लेख है जो गलत है जो कि MANEESHA SAKET होना चाहिए जो सही है जिसके सुधार बावत यह सूचना मेरे द्वारा प्रकाशित कराई जा रही है इस प्रकाशन के माध्यम से मेरे पुत्र स्वतंत्र गय के शैक्षणिक अभिलेखों में माता के नाम की स्पेलिंग MANEESHA SAKET दर्ज की जाए और यही नाम लिखा व पढ़ जाय।
मनीषा साकेत पति संतोष कुमार वर्मा

जीएसटी सुधारों से कारोबार को राहत

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की बैठक में जो फैसले लिए गए, वे समय की मांग थे। इस परिषद का सबसे उल्लेखनीय फैसला इस विभाग के अधिकारियों से गिरफ्तारी के अधिकार को खत्म करने का है। यह फैसला इसलिए उचित है, क्योंकि इसके पहले की वैंट व्यवस्था में भी टैक्स अधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। इस फैसले से कारोबार जगत को राहत मिलेगी, क्योंकि इस अधिकार के चलते सही तरीके से कारोबार करने वाले व्यापारियों में भी

अनावश्यक डर का माहौल बना रहता था। गिरफ्तारी का अधिकार खत्म होने से जीएसटी विभाग का ध्यान टैक्स की वसूली, खातों की जांच और जुर्माने पर ही अधिक रहेगा।

यह भी उचित फैसला है कि यदि फर्जी बिलिंग या टैक्स चोरी का कोई मामला सामने आता है तो उसका निपटारा सामान्य धोखाधड़ी के रूप में किया जाएगा। जीएसटी परिषद ने कुछ अन्य फैसले भी लिए हैं, जैसे 10 दिनों में रिफंड की मंजूरी और 17 दिनों में उसका भुगतान। अब

रिटर्न में किसी तरह की गड़बड़ी के चलते कारोबारियों को कारण बताओ नोटिस से राहत मिलेगी और दस हजार से कम की टैक्स डिमांड पर कारण बताओ नोटिस नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त छोटे ई कामर्स

आपरेटों को अलग-अलग राज्यों में कारोबार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। छोटे कारोबारियों को अब 30 दिनों के अंदर पेनाल्टी देने पर छूट भी मिलेगी। जीएसटी परिषद को अपने फैसलों के सकारात्मक परिणामों पर तो नजर रखनी ही चाहिए। इसी के साथ उसे यह भी देखना होगा कि इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगे।

इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नियम कानूनों में किसी तरह के उल्लंघन का हवाला देकर टैक्स अधिकारी कारोबारियों को तंग करते हैं और उनसे अवैध वसूली करते हैं। कोई भी टैक्स व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो किसी को भी बेवजह तंग न कर सके। इससे ही उद्योग-व्यापार फलेंगे-फूलेंगे और ऐसा होना वक्त की एक बड़ी मांग है। ध्यान रहे कि देश के साथ विदेश के भी कारोबारी टैक्स संबंधी नियमों को सरल और सुगम बनाने की मांग करते ही रहते हैं। यह मांग पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इससे कारोबार जगत में भरोसा बढ़ता है और इसके नतीजे में उसे गति मिलती है। जैसे जीएसटी विभाग से यह

अपेक्षित है कि वह कारोबार को तेजी के साथ फलने-फूलने वाला माहौल बनाए, वैसे ही कारोबारियों के लिए भी यह जरूरी है कि वे नियम-कानूनों के पालन को लेकर प्रतिबद्ध रहें। टैक्स चोरी के मामले धमने ही चाहिए। जीएसटी के नियमों में लगातार सुधार किए जाने के बाद अब इस शिकायत के लिए गुंजाइश नहीं रह जाती कि व्यवस्था जटिल है। समय और तकनीक के साथ कदमताल मिलाना कारोबारियों की भी जिम्मेदारी है।

मेडीकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाना स्वास्थ्य सेवाओं के लिये नुकसानदेह

डॉ योगेन्द्र श्रीवास्तव

पिछले कुछ सालों से देश भर में नये मेडीकल कॉलेज खोलने की होड़ मची हुई है और कोई भी राज्य सरकार पीछे नहीं छूटना चाहती इसलिए जब तब नये मेडीकल कॉलेज खोलने की घोषणाएँ अखबारों की सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने भी 12 और मेडीकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। देश के अन्य राज्यों में भी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार की यही कहानी है और नतीजा यह कि 2014 में 387 से बढ़कर 2026 में मेडीकल कॉलेजों की संख्या 858 हो चुकी है। इसी अवधि में एमबीबीएस की सीटें 51 हजार से बढ़कर एक लाख 1 लाख 40 हजार तथा पीजी की सीटें 31 हजार से बढ़कर 86 हजार हो चुकी हैं। इस बीच महाराष्ट्र आईएमए के प्रदेश सहसचिव डॉ अनुपम ताकलकर का भयान गौरतलब है कि इस बढ़ोतरी पर विराम देने की जरूरत है क्योंकि इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी आशंका है। वाकई इस मामले पर पुनर्विचार एवं गहन मंथन की आवश्यकता है। जनता में लोकप्रियता हासिल करने के लिये राजनेता इस तथाकथित विकास का आश्वासन दे रहे हैं परन्तु वास्तव में यह औचित्यहीन कदम स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर डालने वाला है। दरअसल किसी अन्य शिक्षा संस्थान की तुलना में मेडीकल शिक्षा एकदम अलग है। उदाहरण के लिये एक बहिया तकनीकी संस्थान खोलने में जमीन, भवन, हॉस्टल, प्रयोगशाला, उपकरण तथा शिक्षकों की व्यवस्था करना ही पर्याप्त होता है। लेकिन मेडीकल कॉलेज में इन सबकी व्यवस्था के अलावा एक और अनिवार्य जरूरत होती है कि वहां बड़ी संख्या में मरीज भी आएं। तकनीकी शिक्षा तो किसी उन्नत प्रयोगशाला में ही प्राप्त की जा सकती है जबकि मेडीकल शिक्षा के लिये मरीज एक अनिवार्य फैक्टर है क्योंकि यह पढ़ाई ऐसी है जिसमें छात्रों से मरीज देखने एवं रोग का निदान तथा उपचार करने का ही कार्य करवाया जाता है। अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उक्त छात्र को तजुर्बों के लिये कहीं वास्तविक काम करके व्यावहारिक तजुर्बा लेना पड़ता है जबकि एक नया एमबीबीएस किसी मरीज हुए इन्सान की जान बचा सकता है।

यद्यपि मेडीकल कॉलेज खोलने के लिये निर्धारित न्यूनतम जमीन की शर्त अब हटा दी गई है लेकिन फिर भी इसके लिये काफी ज्यादा जमीन की जरूरत होती है जो आम तौर पर शहरों के बीच उपलब्ध नहीं होती। इसलिए नए मेडीकल कॉलेज शहर से दूर स्थानों पर बनाए जाते हैं। सर्वविदित है कि ऐसे बहुत से नये मेडीकल कॉलेजों में मरीजों का पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिये कहीं कहीं मुफ्त ऑटो या मुफ्त बस सेवा की व्यवस्था की जाती है। फिर भी वांछित संख्या में मरीज नहीं पहुंच पाते। उस पर शिक्षकों का अभाव दूसरी बड़ी समस्या है। मेडीकल शिक्षा की नियामक संस्था एनएमसी के निरीक्षण दौरे के समय शिक्षकों को उपस्थित अवश्य दिखा दिया जाता है लेकिन ये सिर्फ खानापूरी के लिये आते हैं। हालत यह है कि अधिकांश मेडीकल कॉलेज इसी तरह की घोट्टा फैकल्टी (छद्म शिक्षक) से चल रहे हैं। परिणामस्वरूप खूबसूरत बिल्डिंग और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद ऐसे कॉलेजों में एकेडमिक तथा प्रैक्टिकल शिक्षा आधी अधुरी ही हो पाती है। वही हाल पीजी शिक्षण का भी है। इस वजह से बहुत से ऐसे डॉक्टर तैयार किये जा रहे हैं जिनका क्लीनिकल ज्ञान अधूरा है और वे पर्याप्त प्रशिक्षण के बिना ही मरीजों का उपचार करने के लिये अधिकृत हैं। ऐसा नहीं कि एनएमसी को इन सभ्य धांधलियों की जानकारी नहीं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि गैरजरूरी मेडीकल कॉलेज खोलने के राज्य सरकारों के लोकप्रिय अभियान को चालू रखने के लिये एनएमसी भी खानापूरी में पूरा सहयोग दे रही है। वैसे भी देश में वास्तविक स्थितियों को नजरअंदाज करके कागजी कार्रवाई को प्राथमिकता देने की परम्परा है। स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य योजनाओं का भी यही हाल है। उचित गाइडलाइंस के अभाव में अनुष्मान योजना भी दम तोड़ रही है। सरकार अस्पतालों पर दोष मढ़ती है और अस्पताल सालों से लम्बित पड़े करोड़ों के बाकी भुगतान को लेकर लामबंद हो रहे हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र बिल्कुल खस्ताहाल हैं जहां न दवाएं हैं और न ही डॉक्टर। जिला अस्पतालों में भी डॉक्टर और स्टॉफ़ के सैकड़ों पद खाली हैं जिससे वे मरीजों का दवाव झेलने में असमर्थ हैं। लेकिन कागजों पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जारी है जिसमें नए नए मेडीकल कॉलेज खोलना एक शिगूफ़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

बिहार में प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं को लेकर यही मूल सवाल उठ रहा है। पटना, दरभंगा, छपरा, सोनपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मुंगेर और सहरसा जैसे शहरों के आसपास नए शहरी विस्तार की योजनाओं की चर्चा है। सरकार के लिए यह भविष्य के बिहार की शहरी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन किसान के लिए सवाल कुछ और है—जिस जमीन पर उसका वर्तमान टिका है, क्या उसी जमीन पर उसका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा?

कुमार कृष्ण

शहर फैलता है तो सबसे पहले उसकी सीमा नहीं बदलती, किसी किसान की जमीन बदलती है। खेत की मेड़ पर खड़ी किसान अचानक यह सुनता है कि उसकी जमीन अब खेती की जमीन नहीं रही, विकास की जमीन हो गई है। सवाल यही है कि विकास की इस नई परिभाषा में किसान कहा खड़ा है?

किसान विकास का विरोधी नहीं है। वह सड़क चाहता है, अस्पताल चाहता है, स्कूल चाहता है, रोजगार चाहता है और अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन चाहता है। लेकिन वह यह भी चाहता है कि विकास की कीमत उसकी जमीन और आजीविका से ही क्यों वसूली जाए। विकास यदि किसान को उसके खेत से निकालकर केवल मुआवजे का एक चेक थमा देता है, तो यह पूछना स्वाभाविक है कि उसके बाद किसान रहेगा क्या?

भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत लंबे समय से भूमि, कृषि और किसान की हिस्सेदारी के सवाल को आंदोलन के केंद्र में रखते रहे हैं। बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप और भूमि से जुड़े प्रस्तावों पर उठ रही आपत्तियों को इसी बड़े प्रश्न की पृष्ठभूमि में देखना चाहिए। बिहार के सांसद सुधाकर सिंह और किसान नेता दिनेश सिंह जैसे लोगों की मौजूदगी भी बताती है कि मामला केवल जमीन की कीमत का नहीं, बल्कि खेती, गांव और किसान की भविष्य की सुरक्षा का है।

असल बहस यह नहीं है कि बिहार में शहर बनें या नहीं। असली बहस यह है कि शहर किसके लिए और किसकी कीमत पर बनेंगे?

भूमि केवल एक संपत्ति नहीं होती। किसान के लिए वह बैक खाता भी है, रोजगार भी, घर की सुरक्षा भी और अगली पीढ़ी की संभावना भी। एक बीघा खेत से होने वाली आय शायद किसी जमीन की बाजार कीमत से कम दिखाई दे, लेकिन वही जमीन किसान को वषों तक जीवन देती है। जमीन बेचने से एकमुश्त पैसा मिल सकता है, खेती से निर्यात आय मिलती है। इस फर्क को विकास की किसी भी योजना में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यही वजह है कि प्रस्तावित भूमि पूलिंग व्यवस्था को लेकर सवाल गंभीर है। यदि किसान अपनी जमीन विकास के लिए देता है और बदले में विकसित क्षेत्र में कुछ हिस्सा वापस पाता है, तो सवाल उठेगा कि उस लोटाई गई जमीन की वास्तविक कीमत क्या होगी? वह जमीन कहा होगी? उसकी गुणवत्ता क्या होगी? किसान को विकसित भूमि के भविष्य के मूल्य में कितना हिस्सा मिलेगा? क्या उसके अधिकार कानूनी रूप से सुरक्षित होंगे?

किसान को केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं कि जमीन का कुछ हिस्सा वापस मिलेगा। उसे यह भी मादूम होना चाहिए कि क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कहा मिलेगा और उसकी कीमत कैसे तय होगी।

यहीं से पारदर्शिता का सवाल पैदा होता है। सर्किल रेट और वास्तविक बाजार मूल्य में अंतर किसी से छिपा नहीं है। यदि भूमि का मूल्यांकन केवल सरकारी दरों पर होगा, तो किसान को वास्तविक आर्थिक मूल्य का कितना हिस्सा मिलेगा? और यदि आज जिस जमीन की कीमत कम है, वही जमीन कुछ वर्षों बाद करोड़ों की व्यावसायिक संपत्ति बन जाती है, तो उस मूल्यवृद्धि में किसान की कोई हिस्सेदारी होगी या नहीं?

का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितने किलोमीटर सड़क बनेंगी, कितने प्लॉट विकसित होंगे और कितनी इमारतें खड़ी होंगी। यह भी पूछ जाना चाहिए कि कितने किसान विस्थापित होंगे, कितने खेत खत्म होंगे, कितने खेतिहर मजदूर रोजगार खोएंगे और कितने परिवारों की आजीविका बदलेगी? पुनर्वास का अर्थ भी समझना होगा। किसान को पैसा देकर यह मान लेना कि उसका

बनाना चाहती है तो उसे किसानों को योजना का विरोधी नहीं, भागीदार बनाना होगा। किसान से पूछ जाना चाहिए कि वह किस रूप में भागीदारी चाहता है। जमीन के बदले जमीन, विकसित भूमि में हिस्सेदारी, दीर्घकालिक आय, परिवार के एक सदस्य के लिए रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, स्थानीय व्यापार के अवसर या मूल्यवृद्धि में हिस्सा—इन सभी विकल्पों पर सार्वजनिक विमर्श होना चाहिए। भूमि पूलिंग का मॉडल तभी न्यायपूर्ण माना

किसान में सबसे खतरनाक चीज केवल भ्रष्टाचार नहीं होती; अलोकतांत्रिक विकास भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि भ्रष्टाचार की पहचान कभी-कभी हो जाती है, लेकिन ऐसी विकास-व्यवस्था जिसमें जनता की आवाज ही कमजोर कर दी जाए, वह धीरे-धीरे सामान्य लगने लगती है।

राकेश टिकैत का किसान आंदोलन हमें यह याद दिलाता है कि किसान की जमीन को केवल आर्थिक वस्तु मानकर उसकी राजनीति नहीं समझी जा सकती। सुधाकर सिंह जैसे जनप्रतिनिधियों की बहस और दिनेश सिंह जैसे किसान नेताओं की आपत्तियां भी इसी व्यापक चिंता को सामने लाती हैं कि विकास की मेज पर किसान को कुर्सी कहा है।

बिहार की नए शहर चाहिए, लेकिन उससे पहले उसे यह तय करना होगा कि उसके पुराने गांवों का भविष्य क्या होगा।

सरकार को चाहिए कि प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप की पूरी जानकारी सार्वजनिक करे—कितनी जमीन ली जाएगी, कितनी कृषि भूमि प्रभावित होगी, भूमि उपयोग क्या होगा, किसानों को क्या मिलेगा, मूल्यांकन कैसे होगा और पुनर्वास की व्यवस्था क्या होगी। हर परियोजना पर सामाजिक प्रभाव का स्वतंत्र आकलन हो और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। भूमि मालिकों के साथ-साथ खेतिहर मजदूरों, बटाईदरों और अन्य प्रभावित परिवारों के अधिकारों को भी स्पष्ट कानूनी संरक्षण मिले।

किसान के सामने आज सबसे बड़ा सवाल जमीन देने या न देने का नहीं है। सवाल यह है कि जमीन देने के बाद उसका भविष्य किसके हाथ में होगा?

यदि किसान अपनी जमीन देकर शहर बनाता है और उसी शहर में उसके बच्चों के लिए कोई जगह नहीं बचती, तो वह विकास किसका है? यदि खेत की जगह कौनोंनी आती है लेकिन किसान की आय, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा खत्म हो जाती है, तो उसे विकास कहने से पहले लोकतंत्र को ठहकर सोचना चाहिए।

बिहार की मिट्टी ने हमेशा मेहनत को जन्म दिया है। इस मिट्टी को केवल रियल एस्टेट की संभावित कीमत में नहीं मापा जा सकता। किसान को जमीन का मालिक बन नहीं, विकास का नागरिक साझेदार समझना होगा।

आखिरकार सवाल बहुत सीधा है—जमीन हमारी और मालिक कौं और—यह कैसा विकास अधिकार?

शहर बनाना आसान है। नक्शे पर सड़कें खींचना और जमीन को अलग-अलग उपयोगों में बांटना भी आसान है। कठिन काम है ऐसा शहर बनाना जिसमें किसान अपनी जमीन खोकर अपना भविष्य न खो दे।

बिहार यदि सचमुच नया बनना चाहता है तो उसे केवल नए शहर नहीं, नया विकास-संबंध बनाना होगा—जहां सरकार नियोजक हो, किसान साझेदार हो और जमीन केवल बाजार की वस्तु नहीं, समाज की साझा जीवन-पूंजी मानी जाए। यही विकास की असली परीक्षा है।



यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जमीन का इस्तेमाल बदलते ही उसका मूल्य बल्ल बढ़ जाता है। कृषि भूमि जब आवासीय, व्यावसायिक या संस्थागत भूमि में बदलती है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ सकती है। यदि इस परिवर्तन का लाभ केवल डेवलपेर, प्राधिकरण या निवेशक को मिलता है और मूल जमीन मालिक को केवल प्रारंभिक मुआवजा मिलता है, तो किसान विकास का साझेदार नहीं, विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति बनकर रह जाता है।

और लोकतंत्र में इससे बड़ा सवाल क्या हो सकता है कि जिस व्यक्ति की जमीन पर योजना खड़ी हो रही है, उसकी आवाज योजना बनाने समय कितनी सुनी गई?

भूमि अधिग्रहण के मामलों में सामाजिक प्रभाव आकलन का विचार इसी वजह से महत्वपूर्ण रहा है। जमीन जाने का असर केवल जमीन मालिक पर नहीं पड़ता। खेतिहर मजदूर प्रभावित होता है। बटाईदार प्रभावित होता है। सिंचाई का स्रोत प्रभावित होता है। गांव की दुकान, हाट, पशुपालन, स्थानीय परिवहन और खेत के खत्म होने का अर्थ कभी-कभी एक पूरे ग्रामीण आर्थिक तंत्र के कमजोर होने से होता है। इसलिए किसी भी सैटेलाइट टाउनशिप

पुनर्वास हो गया, पुनर्वास की अवधारणा को बहुत छोट्टा कर देना है। खेत खोने वाले परिवार को आवास मिल जाए, लेकिन रोजगार न मिले तो समस्या बनी रहती है। घर मिल जाए, लेकिन बाजार और स्कूल दूर हो जाएं तो जीवन कठिन हो जाता है। जमीन चली जाए और अगली पीढ़ी के लिए कोई आजीविका न बचे तो मुआवजा धीरे-धीरे समाप्त हो सकता है, लेकिन विस्थापन स्थायी रहता है।

कांठ के समय देश ने इसका एक दूसरा चेहरा देखा था। जब शहरों में रोजगार बंद हुआ तो लाखों प्रवासी गांव लौटे। तब गांव और खेती ने उन्हें सहारा दिया। उस संकट ने याद दिलाया कि कृषि भूमि केवल उत्पादन का साधन नहीं, संकट के समय सामाजिक सुरक्षा का आधार भी है।

फिर सवाल यह है कि हम तेजी से फैलते शहरों के लिए गांवों की जमीन लेते समय उस सुरक्षा को कैसे बचाएंगे?

बिहार में शहरीकरण जरूरी है। लेकिन क्या शहरीकरण का मतलब गांवों को निगल जाना है? क्या हर शहर की सीमा बढ़ाने का सबसे आसान रास्ता उसके आसपास की उपजाऊ कृषि भूमि को बल देना है? क्या स्मार्ट शहरों की कल्पना के साथ स्मार्ट गांवों की कल्पना नहीं हो सकती? यदि सरकार सचमुच भविष्य का बिहार

जाएगा जब किसान को यह भरोसा हो कि उसकी जमीन का भविष्य उसके हाथ से पूरी तरह नहीं निकलेगा।

इसके साथ पर्यावरण का सवाल भी जुड़ा है। बिहार की जमीन केवल प्लॉट नहीं है। वह जलसंचय करती है, भूजल को रिचार्ज करती है, बाढ़ के पानी को जगह देती है और स्थानीय पारिस्थितिकी को बनाए रखती है। यदि बड़े पैमाने पर कृषि भूमि को कंक्रीट में बदल दिया गया तो इसका असर केवल खेत तक सीमित नहीं रहेगा। जलभराव, भूजल, गर्मी, बाढ़ और जलनिकासी की समस्या भी बढ़ सकती है।

इसलिए सैटेलाइट टाउनशिप की मास्टर प्लानिंग में किसान के साथ नदी, तालाब, आहर-फर्न, जलनिकाय और कृषि भूमि की भूमिका को भी केंद्र में रखना होगा।

एक और महत्वपूर्ण सवाल शासन-व्यवस्था का है। जिस संस्था के हाथ में इतनी बड़ी मात्रा में जमीन, नियोजन और विकास से जुड़े फैसले होंगे, उसमें जनप्रतिनिधियों, स्वतंत्र विशेषज्ञों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी कितनी होगी? निर्णय प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होगी? कौन जवाबदेह होगा? किसान अपनी आपत्ति किस मंच पर रख सकेगा? क्या ग्रामसभा और स्थानीय निकायों की आवाज निर्णायक होगी या केवल औपचारिक?

कौन-सा राजनीतिक दल किसके पक्ष में.....?

सौरभ वार्धनेय

आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन-सा राजनीतिक दल किसके पक्ष में खड़ा है, बल्कि सवाल यह है कि मतदाता के मन में उठ रहे संदेहों का समाधान कौन करेगा? लोकतंत्र की असली ताकत सत्ता के प्रचार में नहीं, बल्कि जनता के विश्वास में होती है। जब मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर तरह-तरह के सवाल उठने लगें और उनके जवाब स्पष्ट तथा समय पर जनता के सामने न आएँ, तो भ्रम की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है। यह स्थिति किसी एक दल या एक विचारधारा तक सीमित नहीं है।

आज सत्ता पक्ष के पास अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए तमाम साधन हैं। सरकार अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और नीतियों का प्रचार पूरे जोर-शोर से करती है। यह उसका अधिकार भी है। लेकिन लोकतंत्र में केवल सरकार की बात जनता तक पहुंचना पर्याप्त नहीं है। सरकार के निर्णयों पर सवाल उठाने वाले नागरिकों, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को भी अपनी बात रखने का समान अवसर है मिलना चाहिए और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। निर्वाचन आयोग स्वयं मतदाता सेवाओं के लिए नाम खोजने, मतदाता सूची में संशोधन, शिकायत दर्ज करने और अपील जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। वर्तमान में आयोग के पोर्टल पर एसआईआर 2026 से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध हैं। आयोग का घोषित उद्देश्य यह है कि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति उसमें शामिल न हो। फिर सवाल यह है कि यदि व्यवस्था इतनी स्पष्ट है तो मतदाता के बीच भ्रम की गुंजाइश क्यों पैदा हो रही है? यही वह प्रश्न है जिसका जवाब केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं दिया जा सकता। आज चुनाव आयोग को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों और समूहों की ओर से अनेक दावे किए जा रहे हैं। इनमें से कौन-सा दावा तथ्यात्मक है और कौन-सा राजनीतिक आरोप—इसका फैसला जनता को प्रमाण और आधिकारिक जानकारी के आधार पर करना

चाहिए। लेकिन यहां सरकार और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। यदि किसी चुनावी प्रक्रिया को लेकर जनता के मन में संदेह है तो उसका सबसे अच्छा उत्तर यह नहीं हो सकता कि सवाल उठाने वालों को ही कठपौतें खड़ा कर दिया जाए। बेहतर उत्तर है। सभी आकड़े

सार्वजनिक कीजिए प्रक्रिया समझाइए, आपत्तियों का जवाब दीजिए और जहां गलती हुई है, उसे स्वीकार कर सुधार कीजिए। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव प्रक्रिया में उसकी विश्वसनीयता लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयोग स्वयं मतदाता सूची, पंजीकरण, संशोधन और शिकायतों के लिए आधिकारिक माध्यम उपलब्ध कराता है। इसलिए जनता के सवालों का जवाब भी उतनी ही स्पष्टता से आधिकारिक स्तर पर सामने आना चाहिए। आखिर आंदोलन से डर क्यों? दूसरा बड़ा सवाल विरोध और आंदोलन को लेकर है। भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण और बिना हथियार सभा करने का अधिकार देता है। साथ ही संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि इन अधिकारों पर कानून के अनुसार उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसलिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक

असहमति के बीच अंतर करना भी उतना ही जरूरी है। यदि कोई राजनीतिक दल या जनप्रतिनिधि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहता है, तो प्रशासन की भूमिका उसे पूरी तरह रोकने की बजाय ऐसी व्यवस्था बनाने की होनी चाहिए जिससे प्रदर्शन भी हो सके और आम



जनता को असुविधा भी न हो। स्थान निर्धारित किया जा सकता है। समय निर्धारित किया जा सकता है। यातायात की व्यवस्था की जा सकती है। पुलिस बल तैनात किया जा सकता है। सुरक्षा के लिए आवश्यक शर्तें लगाई जा सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर असहमति को कानून-व्यवस्था की समस्या मान लेना लोकतांत्रिक दृष्टि से उचित है? यह प्रश्न आज केवल विपक्ष का नहीं

है। कल यही परिस्थिति किसी दूसरे राजनीतिक दल, किसी सामाजिक संगठन या आम नागरिक के सामने भी आ सकती है। सरकार अपनी आलोचना सुनने की क्षमता भी दिखाए? लोकतंत्र में सरकार केवल इसलिए सरकार नहीं होती कि उसके पास बहुमत है। सरकार की वास्तविक लोकतांत्रिक शक्ति इस बात में भी दिखाई देती है कि वह आलोचना को किस प्रकार स्वीकार करती है। यदि कोई नागरिक सरकार से सवाल पूछता है, तो वह लोकतंत्र के खिलाफ नहीं होता। यदि कोई विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाता है, तो उसके आरोपों की जांच होनी चाहिए। यदि आरोप गलत हैं तो तथ्य सामने रखकर उन्हें खारिज किया जाना चाहिए। यदि कोई शिकायत सही है तो उसका समाधान होना चाहिए। बल्कि कई बार सवाल दबाने की कोशिश ही उस सवाल को और बड़ा बना देती है। आज सोशल मीडिया के दौर में आधी-अधूरी जानकारी कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। ऐसे में आधिकारिक संस्थाओं की चुप्पी या अस्पष्टता अफवाहों के लिए जगह बना सकती है। निर्वाचन आयोग के पास इसका सबसे प्रभावी हथियार है तथ्य, दस्तावेज और पारदर्शी संवाद। मतदाता को राजनीति का नहीं, सत्य का भरोसा चाहिए। भारत का मतदाता राजनीतिक रूप से बेबंद जागरूक है। वह सरकारें बनाता है और बदलता

है। वह नेताओं के भाषण सुनता है, लेकिन अपने विवेक से मतदान करता है। इसलिए मतदाता को किसी दल के पक्ष या विपक्ष में खड़ा करने की बजाय उसे पूरी और सही जानकारी देना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम है या नहीं? नाम हटाय़ा गया तो क्यों? आपत्ति कैसे दर्ज होगी? सुधार कैसे होगा? एसआईआर की प्रक्रिया क्या है? किस दस्तावेज की आवश्यकता है? किस अधिकारी के सामने अपील होगी? समय सीमा क्या है? इन सभी सवालों के जवाब सरल भाषा में घर-घर पहुंचने चाहिए। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और मतदाता सेवा पोर्टल पर नाम खोजें, आवेदन की स्थिति देखने, शिकायत दर्ज करने तथा अपील जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन केवल ऑनलाइन सुविधा पर्याप्त नहीं है। देश के करोड़ों नागरिकों तक सूचना पहुंचाने के लिए राजनीतिक दलों, प्रशासन, मीडिया और निर्वाचन तंत्र को मिलकर काम करना जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग को आलोचना से बचने की बजाय अपने काम की पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है। विपक्ष को भी आरोपों के साथ प्रमाण रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी।

कला उत्सव 2026-27 में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, कोरिया का शानदार प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ की लोककला पंडवानी पर आधारित कुपित याज्ञसेनी को क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम स्थान, राष्ट्रीय कला उत्सव के लिए चयन



मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। कला उत्सव 2026-27 में पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय कोरिया, छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों ने अपनी असाधारण कलात्मक प्रतिभा और सांस्कृतिक समर्पण का परिचय देते हुए शानदार उपलब्धि हासिल की है छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोककला पंडवानी पर आधारित प्रस्तुति कुपित याज्ञसेनी ने क्षेत्रीय कला उत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया है इस उपलब्धि

से विद्यालय परिवार में हर्ष का माहौल है और विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक-सांस्कृतिक विरासत को गौरवान्वित किया है कुपित याज्ञसेनी में पंडवानी के माध्यम से जीवंत हुआ महाभारत का द्रौपदी प्रसंग पारंपरिक कथावाचन की समूह श्रेणी में प्रस्तुत कुपित याज्ञसेनी' महाभारत के द्रौपदी प्रसंग पर आधारित है इस प्रस्तुति में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पंडवानी शैली के माध्यम से न्याय, धर्म, साहस, नारी सम्मान और अटूट

आस्था जैसे भारतीय जीवन-मूल्यों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया कक्षा 11वीं की छात्रा राजनंदिनी सिंह और छात्र विकास कुमार ने अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति, प्रभावशाली कथावाचन और सांस्कृतिक समझ से निर्णायकों को प्रभावित किया इस प्रस्तुति की एक विशेष उपलब्धि यह भी रही कि मुख्य कलाकार राजनंदिनी सिंह ने इसे छत्तीसगढ़ की महान पंडवानी कलाकार पद्म विभूषण तीजन बाई को समर्पित किया तीजन बाई ने अपनी अद्वितीय कला-साधना से पंडवानी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है विद्यार्थियों की इस प्रस्तुति ने उनकी कला-परंपरा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ ही छत्तीसगढ़ की लोक-सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सार्थक संदेश दिया संकुल स्तर पर भी विद्यार्थियों ने हासिल की उल्लेखनीय सफलता कला उत्सव 2026-27 के अंतर्गत संकुल स्तरीय

प्रतियोगिताओं का आयोजन 7 एवं 8 सितंबर 2026 को जवाहर नवोदय विद्यालय, बिलासपुर तथा जवाहर नवोदय विद्यालय, रायगढ़, छत्तीसगढ़ में किया गया। प्रतियोगिता में चित्रकला, मूर्तिकला, स्वदेशी खिलौना निर्माण, पारंपरिक कथावाचन, समूह गायन, समूह नृत्य और शास्त्रीय नृत्य कथक सहित विभिन्न कलात्मक विधाओं में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया संकुल स्तरीय प्रतियोगिता में शास्त्रीय नृत्य कथक की एकल श्रेणी में कक्षा 9वीं की छात्रा डॉली साहू ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया वहीं पारंपरिक कथावाचन की समूह श्रेणी में राजनंदिनी सिंह और विकास कुमार की प्रस्तुति 'कुपित याज्ञसेनी' ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस सफलता ने क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की मजबूत नींव रखी क्षेत्रीय कला उत्सव में प्रथम स्थान के साथ राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची प्रस्तुति संकुल स्तर पर सफलता के बाद क्षेत्रीय कला उत्सव का आयोजन

7 एवं 8 अक्टूबर 2026 को जवाहर नवोदय विद्यालय, कटक, ओडिशा में किया गया यहां भी कुपित याज्ञसेनी ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति से उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रीय स्तर के कला उत्सव 2026-27 के लिए हुआ है यह उपलब्धि विद्यार्थियों की मेहनत, लगन, अनुशासन और कलात्मक प्रतिभा का परिणाम है साथ ही यह भारतीय लोक कलाओं के संरक्षण, संवर्धन और विद्यालयी शिक्षा में सांस्कृतिक गतिविधियों



दोस्त ने ही घर से चुराया डेढ़ करोड़ का सोना, इंदौर पुलिस ने किया खुलासा

मीडिया ऑडिटर, भोपाल (निप्र)। इंदौर के लसुडिया थाना क्षेत्र में घर से सोने के बिस्किट और आभूषण चोरी होने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है मामले में फरियादिया के साथ रहने वाले उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया है पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 630 ग्राम सोने का बिस्किट, 40 ग्राम सोने की चेन, 2 लाख रुपये नकद और एक एप्पल आईफोन 17 सहित लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की है अलमारी में सोना देखकर बनाई चोरी की योजना पुलिस के अनुसार नेपालिया मेन रोड निवासी महिला ने लसुडिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 10 अगस्त से 13 सितंबर 2026 के बीच उसके घर की अलमारी से सोने के आभूषण और सोने का बिस्किट चोरी हो गया। शिकायत के आधार पर पुलिस

ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की जांच के दौरान फरियादिया ने अपने साथ रहने वाले दोस्त गोपाल उर्फ गोपी जाखड़, निवासी जोधपुर, राजस्थान पर संदेह जताया। बताया गया कि घर से जाने के बाद आरोपी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था इसके बाद पुलिस ने उसे अभिरक्षा में लेकर पुछताछ की पुलिस के मुताबिक, पुछताछ में आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया प्रारंभिक पुछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि फरियादिया के घर में रहते समय उसने अलमारी में सोने का बिस्किट देखा था उसके गांव में आगामी महीने सरपंची के चुनाव होने वाले थे और वह चुनाव लड़ने की योजना बना रहा था चुनाव में खर्च और अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए उसने चोरी की योजना बनाई।

आयुष्मान कार्ड से जनन दास को मिला बेहतर उपचार का भरोसा, स्वास्थ्य मंत्री ने सौंपा कार्ड सेवा संकल्प अभियान के तहत पात्र हितग्राही को मिली स्वास्थ्य सुरक्षा की सौगात, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार



मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए जिले में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं इसी कड़ी में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम एवं टीबी मुक्त विकासखंड

सम्मान समारोह के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एमसीबी जिले के विकासखंड खड़वावां निवासी जनन दास को अपने हाथों से आयुष्मान कार्ड प्रदान किया। कार्ड मिलने से जनन दास को स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसा मिला है। योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पात्रता होने

पर उन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के कैंसलस उपचार की सुविधा मिल सकेगी बीमारी के समय बेहतर उपचार उपलब्ध कराना और इलाज पर होने वाले खर्च से परिवारों को आर्थिक राहत दिलाना आयुष्मान भारत योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को निर्धारित नियमों उपचार पैकेज एवं शर्तों के अनुसार सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के कैंसलस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इससे जरूरत के समय पात्र परिवारों को उपचार संबंधी आर्थिक बोझ कम करने और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में सहायता मिलती है। खड़वावां निवासी जनन दास ने आयुष्मान कार्ड मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए इस सुविधा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया कार्ड मिलने से उन्हें भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उपचार की सुविधा प्राप्त करने का भरोसा मिला है सेवा संकल्प अभियान से पात्र हितग्राहियों तक पहुंच रही जनकल्याणकारी योजनाएं सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जनभागीदारी के माध्यम से जनसेवा की भावना को मजबूत करना है अभियान के तहत विभिन्न विभागों द्वारा लोगों को शासकीय योजनाओं की जानकारी देने, पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने तथा उन्हें सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

छूटे हुए मतदाताओं और 17+ आयु वर्ग के युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने विशेष अभियान



मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। मतदाता सूची को अधिक समावेशी एवं अद्यतन बनाने के उद्देश्य से छूटे हुए पात्र मतदाताओं तथा 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है इसी क्रम में मनेन्द्रगढ़ एवं चिरमिरी में वृथ लैबल अधिकारियों (बीएलओ) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशिक्षण के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया तथा अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई मनेंद्रगढ़ में निर्वाचक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार मनेंद्रगढ़ एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार मनेंद्रगढ़ की उपस्थिति में तहसील मनेंद्रगढ़ के बीएलओ का प्रशिक्षण संपन्न कराया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर टी. विजय गोपाल राव ने बीएलओ को विशेष अभियान के अंतर्गत किए

जाने वाले कार्यों की जानकारी देते हुए आवश्यक प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। प्रशिक्षण में छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान करने, संबंधित नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जोड़वाने के लिए जागरूक करने तथा निर्धारित नियमों के अनुरूप पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया गया साथ ही 17 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता बताई गई ताकि पात्रता प्राप्त होने पर वे नियमानुसार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकें इसी क्रम में चिरमिरी में आयोजित बीएलओ प्रशिक्षण बैठक में मास्टर ट्रेनर चंदन दत्ता ने सभी बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अभियान के दौरान अपने-अपने मतदान क्षेत्रों में सक्रियता से कार्य करने तथा पात्र नागरिकों तक मतदाता पंजीकरण संबंधी जानकारी पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया।

मक्के की फसल के बंटवारे पर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की

मीडिया ऑडिटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के रिजौदा गांव में जमीन और मक्के की फसल के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। शुक्रवार को खेत में ट्रैक्टर पर बैठे घनश्याम रघुवंशी (26) पर उसके बड़े भाई चंद्रभान रघुवंशी (34) ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से घनश्याम की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया जानकारी के अनुसार, दोनों सगे भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। करीब छह महीने पहले जमीन का बंटवारा हो चुका था, लेकिन खेत में बोई गई मक्के की फसल के हिस्से को लेकर विवाद बना हुआ था। घनश्याम अविवाहित था और मां के साथ गुना में रहता था फसल के बंटवारे के



सिलसिले में वह गुरुवार को रिजौदा गांव आया था गांव पहुंचने पर घनश्याम अपने बड़े भाई चंद्रभान के घर रुका और वहीं खाना खाकर रात बिताई। शुक्रवार को दोनों फसल के बंटवारे के लिए खेत पहुंचे। इसी दौरान ट्रैक्टर पर बैठे घनश्याम पर चंद्रभान ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया कोलारस थाना प्रभारी पुनीत बाजपेई के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में विवाद हत्या का बंटवारा हो चुका था, लेकिन खेत में बोई गई मक्के की फसल के हिस्से को लेकर विवाद बना हुआ था। घनश्याम अविवाहित था और मां के साथ गुना में रहता था फसल के बंटवारे के

मनेन्द्रगढ़ में खड़ी कार को लगाई आग, वाहन जलकर खाक

सुबह 5 बजे पुरानी नगरपालिका तिराहे के पास हुई घटना, CAIT जिलाध्यक्ष की बताई जा रही कार CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में शुक्रवार सुबह एक खड़ी कार में आग लगने से हड़कंप मच गया आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा वाहन जलकर खाक हो गया कार व्यापारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जिला अध्यक्ष रघुनाथ पौद्धार की बताई जा रही है घटना के बाद आग लगने के कारणों को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं हालांकि कार में जनसूझकर आग लगाए जाने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे पुरानी नगरपालिका तिराहे के पास कार



खड़ी थी इसी दौरान अचानक वाहन में आग लग गई आग ने कुछ ही देर में पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया जब तक स्थिति स्पष्ट होती वाहन बुरी तरह जल चुका था जिला मुख्यालय के व्यस्त इलाके में हुई इस घटना से आसपास के

लोगों में चर्चा का माहौल है प्रारंभिक आशंका है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने कार में आग लगाई हो सकती है हालांकि आग दुर्घटनावश लगी या इसके पीछे किसी की साजिश थी यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल

पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है घटना मनेन्द्रगढ़ सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है पुलिस आसपास के घरों और दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि घटना के समय वहां मौजूद लोगों और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल सके फुटेज के आधार पर आग लगने के घटनाक्रम और संभावित सिलसला का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है फिलहाल पुलिस जांच जारी है आग लगने के वास्तविक कारण और घटना में किसी व्यक्ति की भूमिका को लेकर जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

हाईवे पर धू-धू कर जली कार, डायल-112 ने 7 यात्रियों को सुरक्षित बचाया

अहमदाबाद से उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए जा रहे थे यात्री वाहन के साथ सामान और 8 हजार रुपए की नकदी भी जली



मीडिया ऑडिटर, भोपाल (निप्र)। मध्यप्रदेश के धार जिले में राजोद थाना क्षेत्र के बोरखली के पास हाईवे पर चल रही कार में अचानक आग लग गई वाहन में सात यात्री सवार थे सूचना मिलते ही डायल-112 की दो पुलिस टीमों ने मौके

पर पहुंचकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला आग से कार पूरी तरह जल गई वहीं उसमें रखा सामान कपड़े और करीब 8 हजार रुपए की नकदी भी नष्ट हो गई जानकारी के अनुसार 9 अक्टूबर को डायल-112 पर सूचना मिली कि बोरखली क्षेत्र में हाईवे पर एक कार में आग लग गई है और उसमें सवार लोग फंसे हुए हैं सूचना मिलते ही थाना राजोद की एफआरवी-14 और थाना सरदारपुर की एफआरवी-11 को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि अहमदाबाद से उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने जा रहे यात्रियों की मारुति सुजुकी एर्टेजा कार आग की चपेट में थी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी सात यात्रियों को

सुरक्षित बाहर निकाला आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी कार जल गई वाहन में रखा यात्रियों का सामान कपड़े और लगभग 8 हजार रुपए की नकदी भी आग की भेंट चढ़ गई इसके बाद सभी यात्रियों को दूसरे वाहन से उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया राहत एवं बचाव कार्य में राजोद थाने की एफआरवी-14 के कांस्टेबल प्रकाश (1125) और पायलट तुलसीराम मेडा तथा सरदारपुर थाने की एफआरवी-11 के कांस्टेबल सौरभ मोरे (1210) और पायलट नितेश बाबेरिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही इस घटना में डायल-112 की त्वरित कार्रवाई से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालने में मदद मिली मध्यप्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा संकट के समय नागरिकों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए कार्यरत है।

साइबर ठगी के पीड़ितों को अब मिलेगी कानूनी मदद, ठगी गई रकम की वसूली में भी करेगा विधिक सेवा प्राधिकरण सहयोग

कोरिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बनेगा साइबर कानूनी सहायता प्रकोष्ठ, पैरालीगल वॉलंटियर्स को साइबर अपराध और डिजिटल असेस्ट से बचाव का दिया गया प्रशिक्षण



मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। साइबर ठगी के शिकार लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और ठगी गई राशि

की वसूली की प्रक्रिया में सहयोग देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। साइबर अपराध पीड़ित व्यक्ति को विधिक सहायता एवं

ठगी गई राशि की वसूली योजना 2026 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया में साइबर कानूनी सहायता

प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। यह प्रकोष्ठ पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने से लेकर बैंक, साइबर पुलिस और न्यायलय के स्तर पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई में सहायता प्रदान करेगा इसी कड़ी में साइबर अपराध डिजिटल असेस्ट से बचाव और साइबर सुरक्षा के प्रति आमजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया माननीय उच्चतम न्यायालय के 04 अगस्त 2026 के आदेश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साइबर अपराध पीड़ित व्यक्ति को

विधिक सहायता एवं ठगी गई राशि की वसूली योजना 2026 तैयार की गई है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैकुण्ठपुर में कानूनी सहायता प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य साइबर ठगी के पीड़ितों को समय पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना और उन्हें न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहयोग देना है प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष योगेश पारीक के

मार्गदर्शन तथा प्राधिकरण की सचिव अमृता दिनेश मिश्रा के नेतृत्व में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के सभापार कक्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया साइबर सेल बैकुण्ठपुर कोरिया के विशेषज्ञ शिवम सिंह ने सक्रिय पैरालीगल वॉलंटियर्स को साइबर अपराध, डिजिटल असेस्ट से बचाव और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी प्रशिक्षण के दौरान साइबर धोखाधड़ी से बचाव और आमजनों को जागरूक करने में पैरालीगल वॉलंटियर्स की भूमिका पर भी जोर दिया गया।

संक्षिप्त समाचार

छतरपुर के ढोढ़न बांध पर मजदूरों से भरी बस पलटी



मीडिया ऑडीटर, छतरपुर (निप्र)। छतरपुर जिले के ढोढ़न बांध साइट पर एक हादसा हो गया। केन-बेतवा लिंक परियोजना में काम कर रहे मजदूरों से भरी बस पलट गई। इस घटना में एक अज्ञात मजदूर की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। मजदूर काम खत्म कर घर लौटने के लिए बस में बैठ रहे थे। तभी बस अचानक आगे बढ़ी और पलट गई। घायलों को पहले बिजावर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एनसीसी लिमिटेड कंपनी के 40 से ज्यादा मजदूर बस में थे। घायलों में रमाकांत ठाकुर, वकील चौहान, सुरेंद्र प्रसाद, कृष्णा सिंह, ओमप्रकाश यादव, प्रमोद गौड़, श्याम सुंदर, मुन्नीलाल साहनी, सनी जिसाद, अरविंद, रमेश, विलास्टर साहनी, राहुल सिंह और दीप् शामिल हैं।

प्राकृतिक खेती से बढ़ी आय, वर्मी कंपोस्ट से हर साल 3 से 5 लाख की अतिरिक्त कमाई



मीडिया ऑडीटर, सागर (निप्र)। सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत 'कहानी सेवा की' श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं, सागर जिले के केसली विकासखंड के ग्राम ऊंटकटा टंडा निवासी किसान राघवेंद्र गौड़ की, जिन्होंने उद्यानिकी विभाग की योजनाओं और मार्गदर्शन से पारंपरिक खेती को आय, रोजगार और प्रकृति संरक्षण का माध्यम बनाया है।राघवेंद्र गौड़ पहले पारंपरिक तरीके से खेती करते थे। उद्यानिकी विभाग की योजनाओं और अधिकारियों के मार्गदर्शन से उन्हें कम लागत वाली प्राकृतिक एवं लाभकारी खेती अपनाने की प्रेरणा मिली। विभागीय योजना के अंतर्गत उन्होंने अपने खेत में आम का बगीचा स्थापित किया। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई, जिस पर उन्हें 50 हजार रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। आज राघवेंद्र अपने खेत के गोबर और जैविक सामग्री से वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। इसका उपयोग वे अपनी खेती में करने के साथ बाजार में बिक्री भी करते हैं। इससे उन्हें हर वर्ष लगभग 3 से 5 लाख रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।राघवेंद्र प्राकृतिक पद्धति से अदरक, हल्दी, धान और अरहर जैसी फसलों का उत्पादन करते हैं। उनके खेत में जीवामृत बनाने की यूनिट भी स्थापित है।

नौगांव में चेन स्नेचिंग का आरोपी गिरफ्तार:
पुलिस गिरोह और पुराने मामलों से कनेक्शन की जांच कर रही

मीडिया ऑडीटर, छतरपुर (निप्र)। नौगांव शहर में डूढ़ चेन स्नेचिंग की घटना के बाद पुलिस ने अनुज मिश्रा को गिरफ्तार किया है। अनुज, रमेश चंद्र मिश्रा का बेटा है। वह उत्तर प्रदेश के झांसी के गुरुसाय का रहने वाला है। अभी नौगांव के जेल चौगुहा पर रहता है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ के आधार पर वारदात से जुड़े दूसरे लोगों और घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने यह वारदात अकेले की थी या उसके साथ कोई और भी शामिल था।

सेवा संकल्प अभियान के तहत दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम आयोजित

03 ट्रायसायकल, 06 व्हीलचेयर सहित सहायक उपकरण वितरित, दिव्यांग हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति आदेश भी प्रदान किए

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वावधान में जनपद पंचायत नर्मदापुरम में सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत 'सेवा मेरा योगदान' के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ उन्हें आवश्यक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, श्रीमती प्रीति शुक्ला, श्री राजेश गौर, विधायक प्रतिनिधि श्री सुभाष पटेल, श्री प्रसन्ना हर्षे एवं श्री केशव उर्मिल द्वारा भी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया।

कार्यक्रम की भूमिका और उद्देश्यों पर प्रकाश



खलते हुए अतिथियों ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक शासन की जनकल्याणकारी

योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया ने अपने उद्बोधन में कहा, 'दिव्यांगता नहीं, दिव्यता है पहचान,

सेवा ही हमारा संकल्प महान। सहारा नहीं, सक्षम बनाएंगे-दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाएंगे। उपकरण नहीं, उड़ान दे रहे हैं-आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। '

कार्यक्रम में अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाले एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाशाली दिव्यांगजनों को राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया एवं अन्य अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह एवं शिल्ड/मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मान से दिव्यांगजनों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के साथ उनके हुनर और उपलब्धियों को प्रोत्साहित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिव्यांग हितग्राहियों को मौके पर ही नवीन पेंशन स्वीकृति आदेश वितरित किए गए। वहीं दिव्यांगजनों को सुगम आवागमन एवं दैनिक जीवन में सहूलियत प्रदान

करने के लिए 03 ट्रायसायकल एवं 06 व्हीलचेयर सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए।

कार्यक्रम स्थल पर दिव्यांगजनों द्वारा स्वनिर्मित कलाकृतियों एवं उपयोगी वस्तुओं की विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें मुख्य रूप से डॉ. एनीबेसेंट विशेष विद्यालय एवं छात्रावास तथा भविष्य दिव्यांग विशेष विद्यालय के बच्चों द्वारा तैयार की गई सामग्रियां प्रदर्शित की गईं।

अतिथियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्चों की प्रतिभा, हुनर और आत्मनिर्भरता के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में डिप्टी कमिश्नर एवं उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग सुश्री सीमा बड़ोले, स्सह सुश्री निशा जायसवाल, स्सह श्री सतीश गौतम, जनपद पंचायत के कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन, उनके परिजन एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

ट्रक से 33 क्विंटल डोडाचूरा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार: गेहूं की आड़ में भानपुरा से 8-लेन एक्सप्रेसवे जा रहा था, नारकोटिक्स विभाग ने की कार्रवाई

मीडिया ऑडीटर, गरोठ (निप्र)। मंदसौर जिले के गरोठ-भानपुरा क्षेत्र में नारकोटिक्स विभाग ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से करीब 33 क्विंटल डोडाचूरा जब्त किया है। ट्रक में गेहूं की बोřियों की आड़ में डोडाचूरा छिपाकर ले जाया जा रहा था। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 66 लाख रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। विभाग अब तस्करी के नेटवर्क और मादक पदार्थ की सप्लाई से जुड़े पहलुओं की जांच कर रहा है।

मुख्यबिर् की सूचना पर की घेराबंदी: जानकारी के अनुसार, नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी जेपी मीणा को सूचना मिली थी कि भानपुरा



मार्ग से एक ट्रक में डोडाचूरा की बड़ी खेप दिल्ली-मुंबई 8-लेन एक्सप्रेसवे की ओर ले जाई जा रही है। सूचना की गंभीरता को

देखते हुए उन्होंने विशेष टीम गठित की। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से नाकाबंदी कर संदिग्ध ट्रक को रोक लिया।

गेहूं की बोřियों के पीछे मिले 160 कट्टे ट्रक की तलाशी के दौरान गेहूं की बोřियों के पीछे छिपाकर रखे गए 160 कट्टे मिले। इनमें करीब 32 से 33 क्विंटल डोडाचूरा भरा हुआ था। नारकोटिक्स विभाग की टीम ने मादक पदार्थ जब्त कर लिया। जब्त डोडाचूरा की कीमत करीब 66 लाख रुपए बताई गई है।

तस्करी के नेटवर्क की जांच जारी: कार्रवाई के दौरान पकड़े गए दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विभाग यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि डोडाचूरा कहाँ से लाया गया था और इसे कहाँ पहुंचाया जाना था। साथ ही तस्करी में शामिल अन्य लोगों और संभावित अंतरराज्यीय नेटवर्क के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

जैविक खाद उत्पादन से युवा किसान लक्ष्य चौहान ने बनाई नई पहचान

3 से 4 महीने में 10 टन वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन



मीडिया ऑडीटर, सागर (निप्र)। सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत 'कहानी सेवा की' श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं, सागर जिले के खुई विकासखंड के ग्राम समरंसी निवासी युवा किसान लक्ष्य चौहान की, जिन्होंने उद्यानिकी विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन और शासकीय योजना के सहयोग से जैविक खाद उत्पादन के क्षेत्र में

अपनी पहचान बनाई है। लक्ष्य चौहान ने पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर जैविक खाद उत्पादन को आजीविका का नया माध्यम बनाया। उन्होंने उद्यानिकी विभाग की योजनाओं को जानकारी लेकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए एचडीपीई वर्मीबेड की सहायता से वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की शुरुआत की। उद्यानिकी विभाग के अधिकारी श्री आर.एस. कुर्मी ने

उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया। निरंतर मार्गदर्शन और वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग से लक्ष्य चौहान मात्र 3 से 4 महीने में लगभग 10 टन उच्च गुणवत्ता वाली वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन कर रहे हैं। वे केचुओं के उचित रखरखाव, नमी प्रबंधन, बेड में तापमान सतुलन और गुणवत्तापूर्ण खाद तैयार करने की तकनीकों का पालन करते हैं।स्थानीय किसानों से लेकर गुजरात तक पहुंची जैविक खाद की मांग - लक्ष्य चौहान उत्पादित खाद की आपूर्ति स्थानीय जैविक खेती करने वाले किसानों को करते हैं। खाद की गुणवत्ता और सतुलित पोषक तत्वों के कारण मध्यप्रदेश के साथ-साथ गुजरात में भी इसकी मांग के अनुसार आपूर्ति की जा रही है।

तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर

पैर के पंजे के ऊपर से निकला पिछला पहिया, युवक को राहगीर लेकर पहुंचे अस्पताल

मीडिया ऑडीटर, बड़वाह (निप्र)। बड़वाह में नर्मदा रोड स्थित पूर्णिमा हॉस्पिटल के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक के दाहिने पैर का पंजा कुचल गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, नावचा खेड़ी निवासी प्रकाश पिता पप्पू बड़वाह में अपना काम निपटाकर बाइक से घर लौट रहा था। पूर्णिमा अस्पताल के सामने सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। राहगीर लेकर पहुंचे अस्पताल टक्कर से प्रकाश सड़क पर गिर पड़ा और ट्रैक्टर का पहिया उसके दाहिने पैर के पंजे पर चढ़ गया। राहगीरों ने घायल प्रकाश को तुरंत बड़वाह के सरकारी अस्पताल पहुंचाया।



सीहोर में चलती बाइक पर गिरा तार, जलकर खाक

● आग लगते ही पिता-पुत्र ने कूदकर बचाई जान

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। सीहोर-इछवर मार्ग पर डाकपुलिया के समीप शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा होते-होते टल गया। चलती बाइक पर अचानक 11 केवी हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे बाइक में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त बाइक पर सवार पिता और पुत्र ने तत्परता दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे वे बाल-बाल बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ित पिता के अनुसार वे अपने पुत्र के साथ बाइक पर सवार होकर इछवर रोड से गुजर रहे थे। जैसे ही वे डाकपुलिया के पास पहुंचे, तभी ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन का एक तार ट्रैक्टर सीधे उनकी चलती बाइक पर आ गिरा। तार गिरते ही बाइक में जोरदार



चिंगारी उठी और देखते ही देखते बाइक ने आग पकड़ ली।

पिता-पुत्र ने कूदकर बचाई जान: बाइक पर आग की चपेट में आ गई और धू-धू कर बिजली का तार गिरते और आग की लपटें जलने लगी, लेकिन गनीमत यह रही कि उठते ही पिता और पुत्र ने सूझबूझ का

परिचय दिया और तुरंत चलती बाइक से नीचे कूद गए। हालांकि बाइक पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई और धू-धू कर जलने लगी, लेकिन गनीमत यह रही कि दोनों सवार सुरक्षित बच गए और उन्हें कोई

गंभीर चोट नहीं आई।

सड़क किनारे जलकर खाक हुई बाइक: हादसे के बाद सड़क किनारे खड़ी बाइक आग का गोला बन गई और उसमें से धुएं का गुबार उठने लगा। राहगीरों और आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बाइक काफी हद तक जलकर खाक हो चुकी थी। घटना के कारण कुछ समय के लिए मार्ग पर आवाजाही भी प्रभावित रही।

घटना के बाद स्थानीय लोगों में बिजली विभाग के प्रति गहरा आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से जर्जर और ढीले तारों की शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि समय रहते रखरखाव किया जाता, तो यह बड़ा हादसा टल सकता था। पीड़ितों ने मामले की निष्पक्ष जांच और नुकसान के मुआवजे की मांग की है।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जा रहे विशेष शिविर

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पात्र नागरिक कर सकेंगे फॉर्म-6 जमा

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों पर 7, 8 एवं 9 अक्टूबर को विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। विशेष कैंप के दौरान ऐसे मतदाता, जिनका नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित रह गया है अथवा किसी कारणवश मतदाता सूची से नाम विलोपित हो गया है, वे पुनः नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा पूर्व निवास स्थान से स्थानांतरित होकर आए नागरिक तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवा भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिविरों में पात्र मतदाताओं से फॉर्म-6 प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही, 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की



आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अग्रिम रूप से भी फॉर्म-6 जमा कराए जाएंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए नागरिक ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए voters.eci.gov.in वेबसाइट अथवा ECINET मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फॉर्म-6 के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का घोषणा-पत्र नहीं लिया जाएगा।

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले न्यूजीलैंड के चैपमैन, फाउल्क्स बाहर हुए

ऑकलैंड,एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज से पहले ही मेजबान न्यूजीलैंड को दोहरा झटका लगा है। 22 अक्टूबर से भारत के खिलाफ शुरू होने जा रही पांच मैचों की टी-20 श्रृंखला से पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट के दो प्रमुख खिलाड़ी अनुभवी बल्लेबाज मार्क चैपमैन और तेज गेंदबाज जैक फाउल्क्स, चोटिल होने के कारण पूरी सीरीज से ही बाहर हो गए हैं। यह न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा नुकसान है।

गौरतब है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज चैपमैन को पिछले महीने यूरोपीय टी-20 लीग के दौरान बाएं पांव की मांसपेशियों में खिंचाव आ

क्लाक्सन और टिकनर शामिल



गया था और वह अब तक पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं। वहीं, युवा तेज गेंदबाज फाउल्क्स हाल ही में कैंटरबरी में एक अभ्यास सत्र के दौरान अपने दाहिने कूल्हे में चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गये थे। इन प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति को देखते हुए, न्यूजीलैंड क्रिकेट ने

ऑलराउंडर जोश क्लार्क्सन और तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर को टीम में शामिल किया है। क्लार्क्सन और टिकनर दोनों ही अपनी भूमिकाओं में विशेषज्ञता रखते हैं और टीम को संतुलन प्रदान करने की उम्मीद है।

न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने इस स्थिति पर अपनी चिंता

व्यक्त की और कहा, मार्क और जैक के चोटिल होने से मुझे बहुत दुख है और मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हालांकि, हमें खुशी है कि हम जोश और ब्लेयर जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं, जो इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में खेलने के लिए बेहद उत्साहित हैं। यह पांच मैचों की टी-20 श्रृंखला 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में पहले मुकाबले के साथ शुरू होगी और 1 नवंबर को हैमिल्टन में आखिरी मैच के साथ समाप्त होगी। चैपमैन ने अब तक 113 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और उनके बारे में उम्मीद जताई जा रही है कि वह भारत के खिलाफ आगामी वनडे श्रृंखला तक फिट

होकर वापसी कर सकते हैं। हालांकि, फाउल्क्स की वापसी के लिए कोई निश्चित समयसीमा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, जिससे टीम प्रबंधन चिंतित है। इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड की संशोधित टी-20 टीम में कप्तान मिचेल सैंटनर के साथ फिन एलन, माइकल ब्रैन्सेवेल, जोश क्लार्क्सन, डेवान कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन, मेट हेनरी, बेवन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डैरिल मिचेल, र्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर शामिल हैं। टीम को उम्मीद है कि इन चोटों के बावजूद, वे एक मजबूत प्रदर्शन करेंगे और भारत को कड़ी चुनौती देंगे।

रूस के खिलाफ महिला फुटबॉल टीम ने काफी अच्छा खेला : कोच छेत्री

कोलकाता,एजेंसी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच क्रिस्पिन छेत्री ने कहा है कि उनकी टीम को अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच में भले ही रूस से 0-4 से हार का सामना करना पड़ा है पर उनकी टीम को इससे काफी कुछ सीखने को मिला है। कोच के अनुसार टीम ने काफी अच्छा खेल दिखाया और उसे किसी भी प्रकार से खारिज नहीं किया जा सकता है। मैच के बाद छेत्री ने कहा, मुझे लगता है कि इस मैच की सकारात्मक बात ये है कि एक युवा टीम होने के बावजूद, हमने काफी अच्छा खेल दिखाया। हम दबाव बनाने में पीछे नहीं रहे। हम निडर होकर खेले। हम वही करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में होता है। मुख्य कोच ने टीम के 25-दिवस के शिविर के दौरान खिलाड़ियों द्वारा दिखाए गए सम्पर्ण की भी प्रशंसा की

है। साथ ही कहा कि टीम ने अपनी ओर से काफी प्रयास किये। उन्होंने कहा, सबसे जरूरी बात यह है कि हमने अपना खेल दिखाया और हार नहीं मानी। मेरे लिए यह सबसे अच्छी बात है।



छेत्री ने कहा कि जून से प्रतिस्पर्धी फुटबॉल की कमी रूसी टीम के खिलाफ चुनौतीपूर्ण साबित हुई। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह अनुभव युवा खिलाड़ियों के लिए कीमती होगा क्योंकि वे इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं। 11 अक्टूबर को होने वाले दूसरे फ्रेंडली मैच को देखते हुए, छेत्री ने बताया कि टीम लंबे समय तक अपनी तेजी बनाए रखने की अपनी काबिलियत को बेहतर बनाने पर काम करेगी।

यशस्वी अब विकेटकीपिंग का भी कर रहे अभ्यास



नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आकल बल्लेबाजी और लेग-स्पिन के अलावा विकेटकीपिंग का भी अभ्यास कर रहे हैं, जिससे सभी प्रभावित हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई, जिसमें यशस्वी विकेटकीपिंग का अभ्यास करते दिखे। इसके बाद से ही सभी हैरान हैं कि वह अब क्या करना चाहते हैं। वहीं मुंबई के कप्तान सिद्धेश लाड ने इस रहस्य के बारे में बताया है।

लाड ने खुलासा किया कि, यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी और लेग-स्पिन के अतिरिक्त एक बैक-अप के तौर पर

विकेटकीपिंग का अभ्यास कर रहे हैं। लाड ने इस कदम के पीछे की वजह भी स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यशस्वी को लगता है कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के इस दौर में उन्हें अपने खेल में कुछ और कौशल जोड़ने की जरूरत है। कप्तान ने आगे कहा, मुझे उनके इरादों के बारे में पक्का नहीं पता, लेकिन अभी वह बहुत अभ्यास कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि अगर वह अभ्यास करते रहेंगे, तो उन्हें इसकी आदत हो जाएगी। लाड के इस बयान से साफ है कि यशस्वी क्रिकेट के हर प्रारूप में अपनी उपयोगिता बढ़ाने के लिए यह अतिरिक्त कौशल सीख रहे हैं। गौरतलब है कि भारतीय टीम में हर जगह कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, एक खिलाड़ी का बहु-कौशल वाला होना निश्चित रूप से उसकी टीम में जगह पक्की करने में सहायक हो सकता है। अभी तक यशस्वी को सीमित ओवरों के क्रिकेट में बहुत ज्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने अपना आखिरी एकदिवसीय मैच जून में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, जहां विराट कोहली के रिफ्लेसमेंट के तौर पर शामिल होकर उन्होंने शानदार 110 रन की शतकीय पारी खेली थी। इस प्रदर्शन ने उनकी बल्लेबाजी क्षमता को एक बार फिर साबित किया, लेकिन अब संभावना जताई जा रही है कि अपनी ऑलराउंड क्षमताओं को और निखारने के लिए यशस्वी अब विकेटकीपिंग को भी अपने हुनर में जोड़ना चाहते हैं, ताकि वह टीम के लिए एक अधिक बहुमुखी विकल्प बन सकें।

कुलदीप बन सकते हैं 100 विकेट लेने वाले पांचवें गेंदबाज

रांची,एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव की नजरें यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले दूसरे टी20 में अपने 100 विकेट पूरे करने पर रहेंगी। कुलदीप अभी अपने अंतरराष्ट्रीय टी20 विकेटों का शतक पूरा करने से मात्र तीन विकेट दूर हैं और इसके साथ ही यहां तक पहुंचने वाले भारत के पांचवें गेंदबाज बन सकते हैं। लखनऊ में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपने चार ओवर में 33 रन देकर दो विकेट लिए, जिसके साथ ही उनके टी20 विकेटों की संख्या 97 तक पहुंच गई है। यदि रांची टी20 में कुलदीप तीन और विकेट हासिल करने में सफल रहते हैं, तो वह 100 टी20 विकेट पूरे करने वाले भारतीय टीम के पांचवें गेंदबाज बन जाएंगे। कुलदीप ने अब तक 55 मैचों की 53 पारियों में ये 97 विकेट लिए

हैं, जिसमें दो बार पांच विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है। गौरतलब है भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय टी20 में 100 या उससे अधिक विकेट लेने की उपलब्धि अब तक चार भारतीय गेंदबाज हासिल कर चुके हैं। इनमें अश्विनी सिंह, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल शामिल हैं। कुलदीप अगर यह आंकड़ा छूते हैं, तो वह इस विशिष्ट वलंब के पांचवें सदस्य होंगे। आंकड़ों पर गौर करें तो, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अश्विनी सिंह भारत के लिए टी20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 95 मैचों की 92 पारियों में गेंदबाजी करते हुए कुल 141 विकेट लिए हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं, जिन्होंने 100 मैचों में 126 विकेट अपने नाम किए हैं। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 138 मैचों में 114 विकेटों के साथ तीसरे और बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल 108 मैचों में 111 विकेटों के साथ चौथे पायदान पर हैं। कुलदीप के ठीक बाद, लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल का नंबर आता है, जिन्होंने 80 मैचों में 96 विकेट हासिल किए हैं और वह भी इस ऐतिहासिक वलंब में शामिल होने के करीब हैं। वहीं, अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी 87 मैचों में 90 विकेट लेकर सातवें सबसे सफल भारतीय गेंदबाज हैं।

रणजी ट्रॉफी के लिए जडेजा सौराष्ट्र टीम में शामिल



राजकोट,एजेंसी। अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा रणजी ट्रॉफी 2026/27 सत्र के लिए सौराष्ट्र टीम से खेलेंगे। जडेजा को छत्तीसगढ़ के खिलाफ होने वाले के पहले मैच के लिए सौराष्ट्र की 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। इस टीम का नेतृत्व अनुभवी तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट करेंगे। रणजी ट्रॉफी में खेलने से जडेजा को न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले लय हासिल करने का अवसर मिलेगा। रणजी ट्रॉफी मुकाबले 11 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। इसमें गत चैंपियन सौराष्ट्र को आंध्र, असम, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब और त्रिपुरा के साथ एलीट ग्रुप बी में रखा गया है। वहीं उनादकट की कप्तान में सौराष्ट्र अपने अभियान की शुरुआत राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के खिलाफ करेगा। सौराष्ट्र की टीम में पिछले सत्रन की टीम के 14 खिलाड़ी शामिल हैं। उनादकट ससेक्स के लिए शानदार रहे हैं। उन्होंने सात मैचों में 22.21 की औसत से 28 विकेट लिए हैं। सौराष्ट्र 2025/26 रणजी

ट्रॉफी के दौरान ग्रुप स्टेज में जल्दी बाहर हो गया था और इस साल एक मजबूत कैपेन के लिए बताव है। चयन समिति ने दो नए खिलाड़ियों तेज गेंदबाज नील पांड्या और ऑलराउंडर अर्ध यादव-को टीम में शामिल किया है। हार्दिक देसाई विकेटकीपिंग करते रहेंगे, जबकि बल्लेबाज इकाई में अनुभवी अर्पित वासवदा, चिराग जानी और जय गोहिल होंगे।

उनादकट, लेफ्ट-आर्म पेसर चेतन सकारिया के साथ तेज गेंदबाजी की कप्तान संभालेंगे। अनुभवी लेफ्ट-आर्म स्पिनर धर्मेन्द्रसिंह जडेजा टीम से बाहर हो गए हैं। वह छत्तीसगढ़ की तरफ से खेलेंगे। इसका मतलब है कि इस सीजन में स्पिन बॉलिंग की जिम्मेदारी पार्थ भुट पर होगी। सौराष्ट्र टीम: जयदेव उनादकट (कप्तान), रवींद्र जडेजा, हार्दिक देसाई (विकेटकीपर), अर्पित वासवदा, चिराग जानी, प्रेरक मांकड़, जय गोहिल, चेतन सकारिया, अंकुर पंवार, समर गज्जर, पार्थ भुट, विश्वराजसिंह जडेजा, हेतविक कोटक, नील पांड्या, अर्ध यादव, तरंग गोहेल।

कपिल बोले वैभव को अभी से अगला सितारा नहीं कह सकते, कांबली का दिया उदाहरण

मुम्बई,एजेंसी। पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी अभी 15 साल के ही हैं और ऐसे में उन्हें अगला सितारा कहना जल्दबाजी होगी। कपिल ने वैभव की क्षमता को माना है पर साथ ही कहा है कि उन्हें अभी से सुपरस्टार कहना जल्दबाजी होगी। अपनी बात को मजबूती देने के लिए उन्होंने पूर्व भारतीय बल्लेबाज विनोद कांबली का उदाहरण भी दिया। भारतीय टीम को पहला विश्वकप जितातने वाले इस पूर्व कप्तान के अनुसार वैभव सूर्यवंशी में आगे बढ़ने की पूरी क्षमता है पर कहा कि क्रिकेट के इतिहास में ऐसे कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी सामने आए हैं जिनका



करियर उनकी शुरुआती उम्मीदों के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए, वैभव के लिए अभी से कोई बड़ी भविष्यवाणी करना सही नहीं नहीं है। पूर्व कप्तान ने अपनी बात समझाते

हुए कांबली का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी आए हैं, जिनमें काफी क्षमता थी पर बाद में वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके जिसकी उनसे उम्मीद की गई थी। कांबली का उदाहरण इसी बात को समझाने के लिए दिया गया कि केवल शुरुआती प्रतिभा ही किसी लंबे और सफल करियर की गारंटी नहीं होता। एक खिलाड़ी को लगातार खुद को साबित करना होता है और हर चुनौती का सामना करना होता है। कपिल देव ने वैभव को उग्र का भी खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वैभव अभी सिर्फ 15 साल के हैं और उन्हें अपने खेल व जीवन

को समझने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। कपिल के अनुसार, अगले करीब तीन साल में वैभव की जिंदगी और सोच दोनों में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। इन बदलावों के बाद ही वह बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा कि वह अपने करियर को किस दिशा में आगे ले जाते हैं। कपिल के लिए मैदान पर प्रदर्शन से भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वैभव आने वाले समय में अपने जीवन और करियर को किस तरह संभालते हैं। उन्होंने जोर दिया कि सिर्फ मैदान पर प्रदर्शन देkhना ही काफी नहीं है। खिलाड़ी की सोच, उसकी लाइफस्टाइल और बदलती

परिस्थितियों के बीच खुद को समायोजित करने की क्षमता भी उसके भविष्य को तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है। एक खिलाड़ी को मैदान के बाहर भी उतना ही अनुशासित और फोकस्ड रहना पड़ता है जितना कि वह पिच पर रहता है। फिलहाल, वैभव ने निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा से क्रिकेट प्रेमियों के मन में उम्मीदें जगाई हैं। लेकिन कपिल देव की सलाह साफ है कि इस युवा खिलाड़ी पर अभी से दबाव बनाना या उसे सुपरस्टार का टैग देने के बजाय उसे बढ़ने और सीखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए।

गेंदबाजी आक्रामक में अनुभव की कमी के कारण भुवनेश्वर की वापसी हुई : कोटक

मुम्बई,एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की चार साल के बाद वापसी को लेकर क्रिकेट जगत में चर्चाएं तेज हो गयी हैं। भूवी नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के बाद एक बार फिर 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर वापसी करेंगे। इसी को लेकर भारतीय टीम के

बल्लेबाजी कोच सिताशु कोटक ने बड़ा खुलासा किया है।

कोटक ने कहा कि टीम की मौजूदा गेंदबाजी लाइन-अप में अनुभव की कमी महसूस होने के कारण ही भुवनेश्वर को वापस टीम में बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि इस समय जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज बहुत अधिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, और उनकी अनुपस्थिति में टीम में कई सारे युवा गेंदबाज शामिल हैं। कोटक ने यह भी कहा कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर केवल युवा खिलाड़ियों पर सारी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती है। इससे टीम को उच्च दबाव वाले मुकाबलों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में, एक अनुभवी खिलाड़ी का मार्गदर्शन और मैदान पर उपस्थिति बेहद अहम हो जाती है। कोच ने कहा, मैं अपने विचार अनुसार जवाब दे सकता हूं। इंग्लैंड में, मुझे व्यक्तिगत तौर पर महसूस हुआ कि बुमराह इस समय बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और टीम में कई सारे युवा गेंदबाज हैं पर आपको अनुभव की जरूरत रहती ही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज में जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा नहीं हैं,



और तेज गेंदबाजी आक्रमक की अगुवाई युवा अश्विनी सिंह कर रहे हैं। उनके साथ दूसरे तेज गेंदबाजी विकल्पों के तौर पर मयंक यादव और प्रिस यादव जैसे खिलाड़ी दल में मौजूद हैं, जिनके पास अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक अनुभव नहीं है। कोटक ने साथ ही कहा कि युवा गेंदबाजों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और वे लगातार अच्छा प्रदर्शन भी

कर रहे हैं पर एक निश्चित समय पर, विशेष रूप से बड़े मुकाबलों में, टीम को अनुभवी खिलाड़ियों की स्थिरता और मार्गदर्शन की सख्त आवश्यकता होती है। उन्होंने यह भी बताया कि यह अनुभव ही एक प्रमुख पहलू हो सकता है, जिसकी वजह से भुवनेश्वर को टीम में वापस लाया गया है। इसके अलावा, भुवनेश्वर ने पिछले दो इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन में भी अपनी फॉर्म का प्रदर्शन करते हुए कुल 45 विकेट लिए हैं, जो उनकी मौजूदा लय और विकेट लेने की क्षमता का प्रमाण है। उनकी र्विंग गेंदबाजी और डेथ ओवरों का अनुभव टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है।

इसके साथ ही अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की संभावित वापसी पर भी सिताशु कोटक ने अपनी राय दी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, मैं चयन समिति में नहीं हूं, इसलिए उनकी वापसी पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं पर शमी भी मौजूदा समय में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अगर चयनकर्ताओं को लगता है कि वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो टीम में उनकी आवश्यकता है और निश्चित रूप से उनके नाम पर भी विचार होगा।

कोटक ने यह भी कहा कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर केवल युवा खिलाड़ियों पर सारी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती है। इससे टीम को उच्च दबाव वाले मुकाबलों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में, एक अनुभवी खिलाड़ी का मार्गदर्शन और मैदान पर उपस्थिति बेहद अहम हो जाती है। कोच ने कहा, मैं अपने विचार अनुसार जवाब दे सकता हूं। इंग्लैंड में, मुझे व्यक्तिगत तौर पर महसूस हुआ कि बुमराह इस समय बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और टीम में कई सारे युवा गेंदबाज हैं पर आपको अनुभव की जरूरत रहती ही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज में जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा नहीं हैं,



करते हुए उन्होंने कहा, मैंने पूरे सम्मान के साथ यह फैसला किया है। मुझे शांति और बहुत संतुष्टि महसूस हो रही है। न्यूजीलैंड की तरफ से खेलना मेरे बचपन का सपना था। उन्होंने आगे बताया, यह केवल मेरा सपना ही नहीं था, बल्कि मेरे पिता का भी सपना था। हमें एक मौका दिया और वह

सीनियर मेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप आज से झांसी में शुरू होगी

झांसी,एजेंसी। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 10 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश के झांसी में शुरू होगी। इसमें तीन डिवीजनों में 29 टीमें उतरेंगी। ये टूर्नामेंट 21 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार 2026 सत्र में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी होंगे, जिसमें टीमों को 2025 सत्र की रैंकिंग के अनुसार ग्रुप किया जाएगा। यह चैंपियनशिप देश भर की टीमों को अपनी प्रतिभा दिखाने और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के लिए मुकाबला करने का एक मंच देगी। डिवीजन ए में 12 टीमें होंगी, जिन्हें तीन-तीन टीमों के चार पूल में बांटा गया है। पूल ए में हॉकी पंजाब, हॉकी यूनितेड ऑफ तमिलनाडु और हॉकी बंगाल शामिल हैं, जबकि पूल बी में हॉकी मध्य प्रदेश, हॉकी महाराष्ट्र और हॉकी पुडुचेरी शामिल हैं। पूल सी में उत्तर प्रदेश हॉकी, हॉकी कर्नाटक और हॉकी चंडीगढ़ शामिल हैं, जबकि पूल डी में मणिपुर हॉकी, हॉकी हरियाणा और दिल्ली हॉकी शामिल हैं। पूल के बाद 18 अक्टूबर को क्वार्टर फाइनल होंगे, जिसमें हर पूल से टॉप दो टीमें नॉकआउट स्टेज में जाएंगी। सेमीफाइनल 19 अक्टूबर को होंगे, उसके बाद तीसरे स्थान का मैच और फाइनल 21 अक्टूबर को होगा। डिवीजन बी में दो पूलों में 10 टीमें मुकाबला करेंगी। पूल ए में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा, असम हॉकी, केरल हॉकी, हॉकी उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ हॉकी शामिल हैं। पूल बी में हॉकी झारखंड, तेलंगाना हॉकी, गोवा हॉकी, दारा और नगर हवेली और दमन और दीव हॉकी और हॉकी अरुणाचल शामिल हैं।



करते हुए उन्होंने कहा, मैंने पूरे सम्मान के साथ यह फैसला किया है। मुझे शांति और बहुत संतुष्टि महसूस हो रही है। न्यूजीलैंड की तरफ से खेलना मेरे बचपन का सपना था। उन्होंने आगे बताया, यह केवल मेरा सपना ही नहीं था, बल्कि मेरे पिता का भी सपना था। हमें एक मौका दिया और वह

संक्षिप्त समाचार

रायगढ़ की 9 ग्राम पंचायतों में खेल परिसरों के विकास के लिए 46.32 लाख रुपये स्वीकृत

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विस्तार और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी के प्रयासों से रायगढ़ जिले के तीन विकासखंडों की 9 ग्राम पंचायतों में खेल परिसरों के अहाता निर्माण के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) से 46 लाख 31 हजार 848 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पहले से धरमजयगढ़, घरघोड़ा और तमनार विकासखंडों के ग्रामीण खेल परिसरों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित स्वरूप मिलेगा। बच्चों और युवाओं को खेलकूद, अभ्यास एवं शारीरिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार स्वीकृत सभी निर्माण कार्य वीबी-जी राम जी के अभिस्रण से कराए जाएंगे। इससे डीएमएफ एवं ग्रामीण रोजगार योजना के संसाधनों का समन्वित उपयोग सुनिश्चित होगा। निर्माण कार्यों के दौरान स्थानीय ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस प्रकार यह पहल ग्रामीण खेल अधोसंरचना के विकास के साथ आजीविका संवर्धन में भी सहायक होगी। धरमजयगढ़ की 6 ग्राम पंचायतों में 28.24 लाख रुपये के कार्य धरमजयगढ़ विकासखंड की 6 ग्राम पंचायतों में अहाता निर्माण के लिए लगभग 28.24 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इनमें ग्राम पंचायत खम्हार के लिए 6 लाख 6 हजार 858 रुपये, भोसपुर के लिए 2 लाख 51 हजार 587 रुपये, पुदुक्छर के लिए 51 हजार 587 रुपये के लिए 3 लाख 38 हजार 461 रुपये, कम्माई के लिए 5 लाख 5 हजार 53 रुपये, धोराभांछ के लिए 5 लाख 21 हजार 989 रुपये तथा गनपतपुर के लिए 5 लाख 99 हजार 948 रुपये स्वीकृत किए गए हैं।घरघोड़ा और तमनार में भी विकसित होंगे खेल परिसर घरघोड़ा विकासखंड की दो ग्राम पंचायतों में लगभग 12.40 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इनमें ग्राम पंचायत घरघोड़ी के लिए 6 लाख 12 हजार 322 रुपये तथा कया के लिए 6 लाख 28 हजार 69 रुपये शामिल हैं। इसी प्रकार तमनार विकासखंड की ग्राम पंचायत सरसईपाली में अहाता निर्माण के लिए 5 लाख 67 हजार 561 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार खनन प्रभावित क्षेत्रों में डीएमएफ की राशि का उपयोग जनहित और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए कर रही है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के प्रयासों से रायगढ़ जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खेल सुविधाओं और अधोसंरचना विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले की महत्वपूर्ण उपलब्धि

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ में टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जनभागीदारी, जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जिले की 104 ग्राम पंचायतों को वर्ष 2025 के लिए टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में जिला अस्पताल मोहला में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में टीबी उन्मूलन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित कर प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाना, संभावित मरीजों की समय पर पहचान एवं जांच सुनिश्चित करना तथा उपचाररत मरीजों को नियमित उपचार के लिए प्रोत्साहित करना रहा। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्यकर्ताओं ने टीबी उन्मूलन अभियान को जनभागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी और जनभागीदारी से टीबी उन्मूलन को मिलेगी गतिजिले में टीबी उन्मूलन अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक विकासखंड में अधिकारियों की टीम गठित की गई है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की विकास कार्यो की प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा

कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं के प्रभावी व समयबद्ध क्रियान्वयन पर दिया जोर, जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए निर्देश

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में सरगुजा और सूरजपुर जिले के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विभागीय स्तर पर किए जा रहे कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। सरगुजा के कलेक्टर अजीत वर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल और सूरजपुर की कलेक्टर मती रेना समील भी बैठक में मौजूद थीं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने चारों विभागों के अधिकारियों से योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने तथा कार्यों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का वास्तविक



उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, इसलिए अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने अधिकारियों को अपने कार्यालय की व्यवस्था सुधारने तथा अच्छी साफ-सफाई रखने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं और विकास कार्यों का सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे।

अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें, गम्भीरतापूर्ण ढंग से दायित्वों का निर्वहन करें। उप मुख्यमंत्री साव ने नगरीय क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नगरीय निकायों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारे शहर, हमारे प्रदेश की छवि और जिले की प्रतिष्ठा बनाते हैं।

इसलिए नगरों की व्यवस्था दुरुस्त करें, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि टेण्डर प्रक्रिया होने के बाद तुरंत कार्य शुरू हो जाएं, प्रगतिरत कार्यों को जल्द पूरा करें, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें और अपने दायित्वों का गम्भीरता से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) प्राथमिकता का कार्य है, इसलिए सभी सीएमओ अक्टूबर माह तक प्रगतिरत निर्माण कार्यों को पूरा करें। उन्होंने राजस्व संग्रहण कार्य की हर माह समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, अधोसंरचना मद के कार्यों, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), 15वें वित्त आयोग, रैन वॉटर हार्वेस्टिंग सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 'सड़कों की मरम्मत में लाएं तेजी' उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी

प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बरसात के बाद सड़कों की मरम्मत के कार्यों में तेजी लाने को कहा। साव ने भवनों, सड़कों, पुल-पुलियों तथा अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सड़क एवं अधोसंरचना से जुड़े कार्यों का सीधा प्रभाव आम लोगों के आवागमन पर पड़ता है, इसलिए निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। आने वाला समय ल्योंहारों का समय है, इसलिए समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, लोगों को असुविधा न हो। पेयजल अधोसंरचनाओं के रखरखाव एवं योजनाओं की नियमित निगरानी के निर्देश साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान पेयजल एवं अन्य योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने पेयजल मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, जलापूर्ति से संबंधित कार्यों तथा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने पेयजल व्यवस्था सुचारु बनाए रखने, जल स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पेयजल से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

तन मंत्री केदार कश्यप ने की 60 लाख रुपए के तकनीकी नवाचारों की घोषणा

वन्यप्राणियों के रेटेक्चू के लिए मिलेगा आधुनिक वाहन कांकेर में राज्य स्तरीय वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह का समापन

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने और वन्यप्राणियों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। वन मंत्री केदार कश्यप ने कांकेर में राज्य स्तरीय वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह के समापन समारोह में रेंडियो कॉलरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित निगरानी एवं मोबाइल अलर्ट सिस्टम के लिए 60 लाख रुपए की मंजूरी की घोषणा की। उन्होंने वन्यप्राणियों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए आधुनिक उपकरणों से लैस वाहन उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। वन मंत्री कश्यप ने बताया कि भालू और तेंदुओं की गतिविधियों एवं लोकेशन की निगरानी के लिए



40 लाख रुपए की लागत से रेंडियो कॉलरिंग परियोजना शुरू की जाएगी। वहीं, 20 लाख रुपए की लागत से एआई आधारित मॉनिटरिंग और मोबाइल अलर्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके जरिए वन्यप्राणियों की गतिविधियों की निगरानी के साथ संभावित खतरों की सूचना ग्रामीणों को मोबाइल पर मिल सकेगी। कश्यप ने कहा कि वन्यप्राणियों का

संरक्षण केवल वन विभाग की नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने जनसहभागिता से वन्यजीव संरक्षण का आह्वान किया। वन्यजीवों विमोचन समारोह में वन मंत्री कश्यप ने वन्यजीव संरक्षण, जैव-विविधता और प्राकृतिक विरासत पर आधारित तीन पुस्तकों एवं पुस्तिकाओं का विमोचन किया। बाधिन के दृष्टिकोण से जंगल के अनुभवों को प्रस्तुत करने वाली श्रअचानकमार की जीती-जागती कहानी झुमरी की जुबानीश् तथा गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के प्राचीन शैलचित्रों और पुरातात्विक धरोहरों पर केंद्रित रज्यअसममे प्चतवर्षज्केरु ज्ञनतन ळीपकं ज्जवत च्चदहसं ज्जहमत त्मेमतअमश् शामिल हैं।

माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय मती द्रौपदी मुर्मू के आगामी दिनों में प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। माननीय राष्ट्रपति महोदय का 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक रायपुर एवं जगदलपुर (बस्तर) का प्रवास प्रस्तावित है। मुख्य सचिव ने

अधिकारियों को राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, प्रोटोकॉल, आवास, स्वास्थ्य सुविधा और परिवहन के सभी इंतजाम निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति के संपूर्ण प्रवास कार्यक्रमों के लिए संस्कृति विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। प्रवास के दौरान राष्ट्रपति महोदय के आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम में राजपुर एवं बस्तर संभाग के कलेक्टरों का राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सभी जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

शत्रुघन के परिवार को पीएम आवास न दिया सुरक्षित जीवन

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। कभी बारिश शुरू होते ही घर की चिंता सताने लगती थी। कच्ची दीवारें, खपर की छत और मौसम बदलने के साथ बढ़ती परेशानों के बीच परिवार को सुरक्षित रखने की चिंता बनी रहती थी। रायगढ़ जिले के ग्राम पंचायत बनसिया निवासी शत्रुघन जाटवर के परिवार के लिए यह स्थिति अब बीते दिनों की बात हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिलने से उनके परिवार को न सिर्फ सुरक्षित छत मिली है, बल्कि अपने घर का सपना भी साकार हुआ है। शत्रुघन बताते हैं कि पहले उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था। बारिश के दिनों में घर की स्थिति को लेकर विशेष चिंता रहती थी। तेज बारिश और खराब मौसम में घर और परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती थी। ऐसे में पक्के मकान की उनकी उम्मीद प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरी हुई।

पक्के घर के साथ बदली जिंदगी: पक्का मकान बनने के बाद शत्रुघन और उनके परिवार के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अब मौसम की मार से बचने के लिए उन्हें पहले जैसी चिंता नहीं करनी पड़ती। परिवार को एक सुरक्षित और

स्थायी छत मिली है। शत्रुघन के लिए यह मकान केवल ईंट और सीमेंट से बना घर नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा और बेहतर भविष्य का भरोसा है। वे कहते हैं कि जिन परिवारों के पास कभी रहने के लिए कच्चा खम्पर हुआ करता था, आज उन्हें पक्का मकान मिल रहा है। उनके जैसे जरूरतमंद और आवासहीन परिवारों के लिए यह किसी बड़ी सौगत से कम नहीं है।

घर के साथ मिला सम्मान का एहसास: शत्रुघन का कहना है कि अपना पक्का घर होने से परिवार में सुरक्षा के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा है। पहले जहां बरसात और मौसम की चिंता रहती थी, वहीं अब परिवार निश्चित होकर अपने घर में रह रहा है। उनके लिए यह बदलाव आर्थिक स्थिति से कहीं आगे बढ़कर सम्मान और स्थायित्व से जुड़ा है। शत्रुघन ने पक्का आवास मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गरीब आवासहीन परिवारों के लिए संचालित योजनाओं से उनके जैसे अनेक परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिल रहा है।

पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने की विभागीय योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा, अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश

चित्रकोट को ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने की प्रक्रिया दो सप्ताह में पूरी करने और राम वनगमन पर्यटन परिपथ के 31 नए स्थलों पर दो माह में कार्य शुरू करने के निर्देश

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने आज नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व एवं पुरातत्व विभाग की योजनाओं और विकास कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन विकास से जुड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक स्थलों और समृद्ध जनजातीय संस्कृति को आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से जोड़कर प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए धरतल पर परिणाम दिखाई देने चाहिए।

चित्रकोट को ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी तेज: मंत्री अग्रवाल ने बस्तर के विश्वप्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं दो सप्ताह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित समय-सीमा में डीपीआर एवं प्रोजेक्शन तैयार कर भारत सरकार



के पर्यटन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने को कहा। साथ ही सिरपुर पर्यटन विकास की तैयार डीपीआर का प्रस्तुतीकरण करने के निर्देश दिए। 144 पर्यटन स्थलों का सर्वेक्षण पूरा, 20 स्थलों पर प्राथमिकता से विकसित होगी सुविधाएं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रदेश के 144 पर्यटन स्थलों का गैप फिलिंग असेसमेंट पूरा कर लिया गया है। मंत्री अग्रवाल ने सर्वेक्षण के आधार पर प्राथमिकता वाले 20 पर्यटन स्थलों में सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छ पेयजल एवं अन्य

आवश्यक सुविधाएं फास्ट ट्रैक आधार पर विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन सुविधाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए स्थानीय समितियों को जिम्मेदारी देने अथवा सूलभ इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं का सहयोग लेने को कहा। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के 31 नए स्थलों पर दो माह में शुरू होंगे कार्य मंत्री अग्रवाल ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत पूर्व में विकसित स्थलों के अधूरे कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा निर्मित पर्यटन इकाइयों,

सार्वजनिक शौचालयों और कैफेटेरिया का संचालन स्थानीय समितियों को सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने नवीन चिह्नित 31 स्थलों पर विकास कार्यों के लिए डीपीआर, निविदा और एजेंसी चयन सहित सभी प्रक्रियाएं दो माह के भीतर पूरी कर कार्यादेश जारी करने तथा निर्माण कार्य प्रारंभ कराने को कहा। प्रथम चरण में चयनित 10 स्थलों के अतिरिक्त बस्तर के एक-दो महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल करने तथा आवश्यक बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने माता कोशल्या धाम चंद्रखुरी में प्रभु राम की नवीन प्रतिमा को स्थानांतरित कर मंदिर समिति से चर्चा कर जल्द से जल्द मूर्ति स्थापना के निर्देश दिए। रामलला दर्शन योजना के लिए वैकल्पिक ट्रेन संचालन की व्यवस्था रामलला दर्शन योजना की समीक्षा के दौरान मंत्री अग्रवाल ने कहा कि श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। आईआरसीटीसी द्वारा पेंटी बोगी में तकनीकी समस्या के कारण ट्रेन उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में उन्होंने एक्सप्रेसेशन ऑफ इंटरस्टे (ईओआई) के माध्यम से पृथक एजेंसी चयनित कर वैकल्पिक ट्रेन संचालन की आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भोरमदेव कॉरिडोर की ऑनलाइन निगरानी,

होमस्टे हितग्राहियों को शीघ्र मिलेगी सब्सिडी मंत्री अग्रवाल ने भोरमदेव कॉरिडोर के निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा और तकनीकी निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने तथा संबंधित एजेंसियों को नियमानुसार समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने होमस्टे नीति के अंतर्गत चयनित हितग्राहियों को कैपिटल सब्सिडी शीघ्र उपलब्ध कराने तथा तीन चरणों में सहायता राशि वितरण की आवश्यक तैयारी करने को कहा। पर्यटन मंडल में प्रभु राम की तकनीकी कारणों से निजी संस्थाओं को लीज पर देना संभव नहीं है, उनका संचालन स्थानीय समितियों के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रत्येक पर्यटन इकाई में आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों और उनकी दूरी दर्शाने वाले बड़े सूचना बोर्ड लगाने को कहा गया। पर्यटन मार्गों पर विकसित होंगे सुविधा केंद्र, परियोजनाओं की निगरानी के लिए इंजीनियरों की सेवाएं मंत्री अग्रवाल ने पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रमुख पर्यटन मार्गों पर वेसाइड एमेनिटीज विकसित करने हेतु सभी जिला कलेक्टरों से समन्वय कर भूमि चिह्नित करने और पर्यटन मंडल का लैंड बैंक तैयार करने के निर्देश दिए।